कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

कार्तिक–मार्गशीर्ष 2079, नवंबर 2022

जीएम सरसों
जरूरत या मुसीबत

स्वदेशी मेला

जमशेदपुर, झारखंड

सचित्र झलक

देहरादून, उत्तराखंड

स्वावलंबी भारत अभियान

नोएडा, उत्तर प्रदेश

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–30, अंक–11
कार्तिक–मार्गशीर्ष 2079 नवंबर 2022

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **35-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06
जीएम सरसों: जरूरत या मुसीबत
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 **आवरण कथा–2**
डरा रहा है सरसों का नया अवतार ..... अनिल तिवारी

11 **आवरण कथा–3**
जीएम फसलः छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान तो नहीं ! ..... अरविन्द कुमार मिश्रा

14 **विश्लेषण**
स्वावलम्बन का आधार स्वदेशी ..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल

16 **बीच–बहस**
आक्रामक चीन और भारत के हित ..... के.के. श्रीवास्तव

18 **स्वास्थ्य**
गर्भपात का अधिकारः कानूनी दांव पेच से आगे ..... डॉ. जया कक्कड़

20 **मूल्यांकन**
भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का हाल ..... अनिल जवलेकर

22 **मुद्दा**
खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुकसान को रोकना आज की आवश्यकता ..... स्वदेशी संवाद

24 **समीक्षा**
ऐतिहासिक करवट के प्रतीक ऋषि सुनक ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

26 **आजकल**
विकसित देशों की तुलना में भारत में तेजी से कम हो रही है गरीबी ..... प्रहलाद सबनानी

28 **मीडिया**
विदेशी मीडिया में भारत विरोधः कारण और निवारण ..... विनोद जौहरी

30 **स्मरणांजलि**
मजदूरों दुनिया को एक करोः दत्तोपंत ठेंगड़ी ..... हेमेंद्र क्षीरसागर

32 **अपील**
'ज्ञान और दान बांटने की सनातनी परंपरा' प्रवासी भारतीयों से किया आह्वान ..... डॉ. जयप्रकाश मिश्र

पाठकनामा

गहराते खाद्य संकट का हल खोजे दुनिया

विभिन्न रिपोर्टों एवं आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि विश्व में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। फसल चक्र अनियमित और असंतुलित होता जा रहा है। जिससे सारे विश्व के लिए खाद्य सुरक्षा एक अहम चुनौती के रूप में दिख रही है। एक अनुमान के अनुसार 2040 तक तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ता है तो फसलों की पैदावार पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भारत के कुछ हिस्सों में इस बार अतिशय बरसात के कारण समय से धान की खेती नहीं हो पाई, वहीं एक बड़े इलाके में पानी के अभाव में खेती पर बुरा असर पड़ा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में अबकी खेती समय से नहीं शुरू हो सकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खरीफ की फसल न के बराबर रही है। कई विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से इस शताब्दी में विश्व में झगड़े, भुखमरी, बाढ़ और जनसंख्या के पलायन में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए भविष्य में दुनिया के सभी देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करना होगा। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कृषि पद्धतियां पूरी तरह मौसम की परिस्थितियों पर आधारित होने के कारण दक्षिण एशियाई देशों में कृषि के पैदावार में आने वाले वर्षों में 30 से 40 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

जाहिर है कि इसी तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे तो कृषि पर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता जाएगा। जिससे अधिकांश जनसंख्या के लिए रोजी–रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं 2030 तक भूख को खत्म करने का हमारा लक्ष्य भी अधूरा रह जाएगा। बिगड़ते जलवायु के कारण फसलों में पोषक तत्वों और प्रोटीन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण संतुलित व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना दिवास्वप्न मात्र बनकर रह जाएगा। भारत के लिए और ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि हमारे देश की 70 प्रतिशत जनता खेती से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। कृषि उनके जीवन का मुख्य स्रोत है। भारत की जनसंख्या अभी 1.04 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ रही है। 2030 तक यह जनसंख्या डेढ़ अरब तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में अभी भी अनेक समस्याएं हैं।

जयेंद्र नाथ मिश्र, ग्राम–लक्ष्मीपुर, पोस्ट–मून छपरा, जिला–बलिया (उ.प्र.)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल:
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना जरूरी है। भारत में जातियों, धर्मों और वर्गों का एक विविधतापूर्ण समावेश है। अगर समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार नहीं किया जाता है, तो देश या समाज को पूरी तरह से विकसित नहीं कहा जा सकता है।

द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत

वड़ोदरा में विमान निर्माण सुविधा विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

देशी भाषाओं में शिक्षा भारत की क्षमता को पूरी तरह से खोल देगी। यदि किसी को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, तो उसकी बौद्धिक क्षमता के उज्जवल होने का बेहतर मौका होता है।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

यह दावा कि जीएम सरसों (डीएमएच–11) स्वदेशी और सुरक्षित है, पूरी तरह से गलत है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

ऋषि सुनक के समक्ष आर्थिक चुनौतियां

भारतीय मूल के ऋषि सुनक द्वारा आर्थिक संकट से जूझ रहे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालते ही, यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि इस संकट का ऋषि सुनक क्या हल निकालेंगे? पिछले महीनों में 27 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट के साथ 26 सितंबर 2022 तक डालर के मुकाबले ब्रिटिश पाऊंड इतिहास में अभी तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। उसके बाद पिछले एक महीने में 6.5 प्रतिशत तक बेहतर हुआ है। इंग्लैंड का विदेशी मुद्रा भंडार, मात्र कुछ हफ्तों के आयातों के लिए ही हैं। एक तरफ पाऊंड डालर के मुकाबले में लगातार गिर रहा है, वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड (केन्द्रीय बैंक) के लिए, विदेशी मुद्रा भंडारों में भी आ रही गिरावट के चलते पाऊंड को और अधिक गिरने से बचाने में मुश्किल होता जा रहा है। 1976 में जब एक पाऊंड, दो अमरीकी डालर के बराबर था, और उसमें कमजोरी आ रही थी, तब इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 3.9 अरब डालर का ऋण लेकर उसे थामने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब पाऊंड, एक अमरीकी डालर की ओर आगे बढ़ रहा है। इंग्लैंड के पास ऐसा कर पाने का सामर्थ्य ही दिखाई नहीं दे रहा।

अर्थव्यवस्था में अगस्त माह तक जीडीपी 0.3 प्रतिशत की गिरावट रिकार्ड हो चुकी थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुमानों के अनुसार भी 2023 में जीडीपी ग्रोथ अधिक से अधिक 0.3 प्रतिशत की ही वृद्धि अपेक्षित है। इस वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ 0.7 प्रतिशत रही, जो दूसरी तिमाही में घटकर 0.2 प्रतिशत, जुलाई में 0.1 प्रतिशत और अगस्त में और घटते हुए ऋणात्मक 0.3 प्रतिशत हो गई थी, यानि अर्थव्यवस्था 0.3 प्रतिशत सिकुड गई। पिछले माह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में महंगाई की दर 10.1 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और यूक्रेन युद्ध के चलते तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने के कारण ईंधन की कीमतें 3 गुणा तक बढ़ चुकी हैं। आगे आने वाली सर्दियों में ब्रिटेनवासी मुश्किलों का सामना करने के लिए बाध्य होंगे। समझा जा रहा है 30 प्रतिशत इंग्लैंड वासियों की बचत समाप्त हो चुकी है और सरकारी कर्ज भी, जीडीपी के 95 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो एक रिकार्ड है। एक गैर सरकारी संस्थान का कहना है कि 50 सालों में यह सरकारी कर्ज जीडीपी के 320 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

प्रधानमंत्री के नाते चयनित होते ही ऋषि सुनक ने सीधेतौर पर कहा कि गंभीर संकट में फंसी अर्थव्यवस्था का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पूर्व प्रधानमंत्री ट्रस द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में उन्होंने कहा कि गलतियां हुई हैं, लेकिन उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उन्हें इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु चुना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे सरकार को ईमानदारी, पेशेवर तरीके से और जवाबदेही के साथ चलायेंगे।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस ने आयकर की दर घटाने और कमजोर वर्गों को राहत देने के उद्देश्य से बजट प्रावधान करने के कुछ निर्णय लिए थे, जिसके कारण सरकार द्वारा भारी कर्ज लेने का खतरा मंडराने लगा, जिसके चलते सरकार की साख इतनी अधिक प्रभावित हुई कि 26 सितंबर 2022 तक 30 वर्षीय बांड़ की कमाई 4.95 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। हालांकि इसके बाद इसमें सुधार होते हुए यह 3.75 प्रतिशत तक घट गई है। लिज़ ट्रस ने अपने बजट में लोगों को मंहगाई से राहत देने के लिए सरकारी करों में भारी रियायत देने की योजना प्रस्तुत की थी। उनका कहना था कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और लोगों को मंहगाई से राहत। उन्होंने 45 अरब पाउंड की टैक्स कटौती की बात की थी। ऐसे में बाजारी शक्तियों ने इसे सही कदम नहीं माना और बाजार में अस्थिरता व्याप्त हो गई और वित्तीय मंदी के हालात पैदा हो गये। ऋषि सुनक ने लिज़ ट्रस को चेताया था कि वे खर्च पर लगाम लगाये और करों में कटौती न करें। ऋषि सुनक का यह कहना है कि मंहगाई से निकलने के लिए उधार का रास्ता अपनाना सही नहीं है। अब जब पहले कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने ऋषि सुनक के मुकाबले लिज़ ट्रस को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया था, उन्हीं सांसदों ने अब ऋषि सुनक को सत्ता सौंपी है। केवल सरकारी ऋण ही नहीं, अर्थव्यवस्था की रिकवरी भी बढ़ती ब्याज दरों के कारण मुश्किल हो गई है। उधर पहले से ही आम जनता बढ़ती कीमतों के कारण घटती क्रय शक्ति से जुझ रही है। बढ़ती ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों ने मध्यम वर्ग का बजट पहले से ही बिगाड़ दिया है। ऐसे में मॉर्टगेज कंपनियों की वसूली भी प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है।

गौरतलब है कि टैक्स घटाने, खर्च बढ़ाने और उधार लेने की नीति के प्रबल विरोधी सुनक मानते हैं कि यह 'कंजर्वेटिव' सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और इसे समाजवाद ही कहा जायेगा। सुनक की योजना है कि उधार टैक्स को वर्तमान 20 पैसे प्रति पाउंड से घटाकर 16 पैसे प्रति पाउंड किया जाये (20 प्रतिशत कटौती)। 2024 तक आयकर को 1 प्रतिशत घटाया जाये, घरेलू ईंधन बिल में कटौती हो और कारपोरेट टैक्स को 2023 तक बढ़ाया जाये। बजारों की स्वीकार्यता की दृष्टि से सुनक की योजना लिज़ ट्रस की नीतियों से अधिक बेहतर दिखाई देती है। देखना होगा कि वे अपनी योजना को वास्तविकता का जामा कैसे पहनाते हैं। लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि सुनक का आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ उन्हें ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को संभालना है तो दूसरी ओर 'लेबर पार्टी' की बढ़ती लोकप्रियता के कारण 'कंजर्वेटिव पार्टी' के लिए जन समर्थन को भी बरकरार रखना है। ❑

जीएम सरसोंः जरूरत या मुसीबत

अक्टूबर 18, 2022 को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक समिति जैनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (यानि जीईएसी) ने जीएम सरसों की एक किस्म डीएमएच–11 को एक बार फिर से किसानों के खेतों में लगाने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि इससे पहले मई 2017 में भी जीईएसी ने इसी किस्म को अपनी हरी झंडी दी थी। लेकिन इसका किसानों और वैज्ञानिकों द्वारा भारी विरोध होने के कारण सरकार ने जीईएसी की सिफारिशों को मानने से मना कर दिया था। लेकिन 18 अक्टूबर 2022 की बैठक में जीईएसी ने पुनः इसकी सिफारिश कर दी है। यह बताया जा रहा है कि यह किस्म प्रो. दीपक पेंटल द्वारा देश में ही विकसित की गई है और पूर्णतया स्वदेशी है। यह भी दावा किया जा रहा है कि यह जीएम सरसों 26 प्रतिशत अधिक उपज देगी। यह भी बताया जा रहा है कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन कम है, जिसके कारण देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जीएम सरसों उपभोक्ताओं, किसानों और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है।

लेकिन जीईएसी के इन दावों की सच्चाई कितनी है, वो इस बात से स्पष्ट हो रही है कि स्वयं जीईएसी ने जीएम सरसों को अनुमति देते हुए कुछ ऐसी शर्तें लगाई हैं, जो इस बात को साबित करती हैं कि जीईएसी के पास इस बीज के सुरक्षित होने के कोई प्रमाण नहीं है, और वे शर्तें लगाकर इससे होने वाले दुष्प्रभावों के आरोप से बचना चाहती है, कि भविष्य में वो कह सकें कि हमने जीएम सरसों को कुछ शर्तों के साथ ही अनुमति दी थी और चूंकि उन शर्तों का पालन नहीं हुआ इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। गौरतलब है कि जो शर्तें लगाई गई हैं उनका अनुपालन करना सरकार के बस की बात नहीं है।

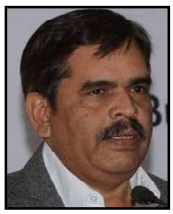

देश में जहां जीएम खाद्य पदार्थों की कोई जरूरत नहीं है, व्यवसायिक ताकतों के दबाव में इनको दी जाने वाली अनुमतियों से देश की खेती–किसानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं निर्यातों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इस मामले में जीईएसी की सिफारिशों को दरकिनार कर देशहित की रक्षा करें।
– डॉ. अश्वनी महाजन

यह किस्म नहीं है स्वदेशी

जीईएसी के इस दावे में सत्यता नहीं है कि डीएमएच–11 एक स्वदेशी खोज है। वर्ष 2002 में बॉयर (एक विदेशी कम्पनी) की एक सहायक कंपनी 'प्रोएग्रो सीड कंपनी' ने इसी प्रकार की किस्म, जिसे डीएमएच–11 कहा जा रहा है की अनुमति हेतु आवेदन किया था, जिसे आईसीएआर यानि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने यह कह कर मना कर दिया था कि इससे बेहतर उत्पादकता मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। वास्तव में डीएमएच–11 किस्म बारनेस और बारस्टार नाम के दो जींस को जोड़कर बनाई गई है और ये जीन्स बॉयर क्रॉप साईंस द्वारा पेटेंट की गई है। ऐसे में इस तथ्य को छुपाया गया है और भविष्य में बॉयर कंपनी अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों की एवज में भुगतान मांग सकती है और भारत के किसान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

ऊंची उत्पादकता का गलत दावा

गौरतलब है कि डीएमएच–11 के बारे में जीईएसी का ज्यादा उत्पादकता का दावा सही नहीं है, क्योंकि भारत के सरसों एवं रेपसीड शोध संस्थान का कहना है कि देश में डीएमएच–11 से कम से कम 25 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादकता देने वाली किस्में पहले से ही विकसित की जा चुकी हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उन किस्मों को बढ़ावा दे।

खतरनाक है जीएम सरसों

खेद का विषय यह है कि केवल इस प्रौद्योगिकी के विदेशी मूल को ही नहीं छुपाया गया, बल्कि यह तथ्य भी छुपाया गया कि जीएम सरसों हर्बीसाईड टोलरेंट भी है यानि शाकनाशी सहिष्णु भी है। गौरतलब है कि डीएमएच–11 का ट्रायल करते हुए उसकी इस विशेषता के बारे में कोई टेस्ट नहीं किया गया। इस बात को जानने वाले सतर्क नागरिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा सच्चाई को सामने लाए जाने के कारण अब जीईएसी ने एक नया रास्ता खोजा है कि अनुमति के साथ–साथ यह शर्त लगाई गई है कि किसी भी हालत में किसानों द्वारा किसी शाकनाशी का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब चूंकि यह किस्म ही शाकनाशी सहिष्णु है, स्वभाविक तौर पर शाकनाशियों की पर्याप्त उपलब्धता होने के कारण कोई सरकारी एजेंसी किसानों को इसके बारे में रोक नहीं सकती। इस संबंध में एक समानान्तर उदाहरण हमारे सामने है कि 'ग्लाइफोसेट' नाम के शाकनाशी का उपयोग हालांकि केवल चाय बागानों और गैर कृषि क्षेत्रों में ही हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद देशभर में यह शाकनाशी धड़ल्ले से बिकता है और भारत में उसकी कुल बिक्री 1200 करोड़ रूपए से ज्यादा है। समझा जा सकता है कि जीईएसी का यह कृत्य वास्तव में अनैतिक है। गौरतलब है कि कई प्रकार के शाकनाशकों के दुष्परिणामों से दुनिया जूझ रही है। इन शाकनाशकों के कारण अमरीका और अन्य मुल्कों जहां इस प्रकार की किस्मों का इस्तेमाल हो रहा है, में कैंसर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इन शाकनाशकों की निर्माता कंपनियों पर मुकदमें भी लगातार बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि सिर्फ ग्लाइफोसेट/राउंडअप बनाने वाली कंपनी बॉयर के खिलाफ अमरीका में कैंसर पीड़ितों द्वारा 1 लाख 40 हजार मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

इस प्रकार से यह समझते हुए भी कि शाकनाशी सहिष्णु क़िस्म का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, यह वैज्ञानिक धोखा है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है।

भारतीय सरसों है आयुर्वेद में वरदान

कई आयुर्वेदिक औषधियों में भारतीय सरसों एक वरदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसकी खुशबु एवं स्वाद ही इसकी विशेषताएं हैं। जानकार बताते है कि डीएमएच–11 में न तो खुशबू होगी और न ही स्वाद यानि इसमें औषधीय गुण होने का सवाल ही नहीं है। यही नहीं स्वाद की दृष्टि से देश में सरसों का साग पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। शाकनाशी सहिष्णु का उपयोग करते हुए जब डीएमएच–11 भारत की सरसों के बदले में उगाई जाएगी, तो देश में केवल सरसों का साग ही विलुप्त नहीं होगा, बल्कि सरसों के साग के साथ उगने वाले अन्य साग जैसे बथुआ और पालक भी गायब हो जाएंगे। गौरतलब है कि ये साग लगभग मुफ्त में हमारी महिलाओं द्वारा खेतों से निकाले जाते हैं और वे भारत की महिलाओं के लिए आयरन का एक प्रमुख स्रोत है। इनके समाप्त होने से देश में एनीमिया की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है।

निर्यात पर भी पड़ेगा बुरा असर

एक तरफ जहां यह कहा जा रहा है कि इस किस्म के लगाने से देश में खाद्य तेलों का आयात कम हो जाएगा, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस किस्म के आने से देश में शाकनाशकों का आयात जरूर बढ़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत की बात यह है कि देश में खाद्य पदार्थों में जीएम आने के बाद देश के खाद्य निर्यातों पर भारी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि अभी तक अपने देश में खाद्य पदार्थों में जीएम को अनुमति नहीं दी गई है। देश में सभी उत्पादित खाद्य पदार्थ गैर–जीएम हैं। देश के खाद्य निर्यात में गैर–जीएम का यह टैग यूरोप समेत कई मुल्कों में हमारे खाद्य पदार्थों की स्वीकार्यता को बढ़ाता है। खतरा यह है कि जैसे ही गैर–जीएम का यह टैग भारत के निर्यातों से हट जाएगा, भारत के निर्यात बड़ी मात्रा में बाधित हो जाएंगे, क्योंकि युरोप और अन्य कई देश उन्हीं देशों से खाद्य पदार्थ ख़रीदना चाहते हैं जो जीएम का उत्पादन नहीं करते। गौरतलब है कि आज भारत लगभग 50 अरब डालर के खाद्य पदार्थों का निर्यात करता है। देश इन निर्यातों को बाधित करने का खतरा नहीं उठा सकता। अगर ये निर्यात बाधित होते हैं तो किसानों की आमदनी को बढ़ाने की संभावनाएं तो समाप्त होंगी ही बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी हानि होगी।

कई आयुर्वेदिक औषधियों में भारतीय सरसों एक वरदान के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसकी खुशबु एवं स्वाद ही इसकी विशेषताएं हैं। जानकार बताते है कि डीएमएच-11 में न तो खुशबू होगी और न ही स्वाद यानि इसमें औषधीय गुण होने का सवाल ही नहीं है।

कहा जा सकता है कि देश में जहां जीएम खाद्य पदार्थों की कोई जरूरत नहीं है, व्यवसायिक ताकतों के दबाव में इनको दी जाने वाली अनुमतियों से देश की खेती–किसानी, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं निर्यातों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इस मामले में जीईएसी की सिफारिशों को दरकिनार कर देशहित की रक्षा करें। ❑❑

डरा रहा है सरसों का नया अवतार

जीएम सरसों को लेकर एक तरफ सेहत संबंधित चिंता है तो दूसरी और इसके पक्ष और विपक्ष में लाबिंग भी है, जो बाजार पर कब्जा करने के लिए लगातार की जा रही है। भारत के लिए यह कोई नया बवाल नहीं है। पहले भी बीटी कॉटन और बीटी बैगन को लेकर पक्ष–विपक्ष की भिड़ंत हो चुकी है। स्वदेशी जागरण मंच सरीखे संगठनों के पुरजोर विरोध के कारण हर बार सरकारों को अपने पैर खींचने पड़े। केंद्र सरकार के नियामक ने एक बार फिर सरसों के प्राचीन पारंपरिक उत्पादक देश में विकसित जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम बीजों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी है। सरसों के जिस किस्म के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी गई है उसे वरुण नाम की पारंपरिक सरसों की प्रजाति और यूरोप की एक प्रजाति के साथ क्रास करके बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इससे सरसों के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी। कृषि, जलवायु और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों की आपत्ति और कई जन संगठनों के भारी विरोध के बीच यह मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा है, जहां उच्चतम न्यायालय ने जन भावनाओं का ख्याल करते हुए इसके आगे बढ़ने पर रोक लगा रखी है।

देश दुनिया की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसकी तुलना में हमारा कृषि उत्पादन लगातार घट रहा है। कई एक कृषि वैज्ञानिक आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट की आशंकाओं को देखते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों की जगह जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की खेती पर जोर दे रहे हैं। ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल फिलहाल इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन ठीक इसके उलट हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन लगातार यह कहते रहे हैं कि जीएम फसलों को मंजूरी देने से हमें बचना होगा। डॉ. वंदना शिवा जैसे कई पर्यावरणविदों ने कहा है कि इस तरह के मामलों के निर्णय भावनात्मक नहीं बल्कि तर्कपूर्ण विवेचना के साथ होने चाहिए, क्योंकि भोजन, आजादी और न्याय का भी मसला होता है।

'स्वदेशी पत्रिका' अपने पाठकों के लिए इस मसले से जुड़े प्रमुख बिंदुओं को लेकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की है कि यह मसला कितना जरूरी है और कितना गैरजरूरी है? दरअसल यह राहत है या आफत?

'हमारा देश प्राचीन काल से ही पारंपरिक खेती का देश रहा है। वर्तमान सरकार ऑर्गेनिक खेती पर जोर दे रही है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के इशारे पर इस तरह की जहरीली खेती के लिए जगह बनाना, किसी रहस्य से कम नहीं है।

– अनिल तिवारी

जीएम फसलें क्या होती हैं और इसे कैसे तैयार किया जाता है?

डॉ. आलोक दत्त ने बताया कि जीएम फसल का मतलब होता है वैसी फसल जिसे वैज्ञानिक मूल फसल के डीएनए में थोड़ा बहुत बदलाव करने के बाद तैयार करते हैं। इसके जरिए फसल में कीटनाशकों से लड़ने की क्षमता विकसित की जाती है। अब तक वैज्ञानिकों

ने सोयाबीन, मक्का, कपास, चुकंदर, चावल, आलू, टमाटर, मूंगफली, सरसों, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, भिंडी, गेहूं, बासमती चावल, सेव, केला, पपीता, प्याज, तरबूज, अदरक जैसी फसलों के साथ इस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी जीव की पहचान उसके डीएनए से होती है। डीएम ने एक लंबा और दोहरे स्तर वाला कण होता है, जो अलग–अलग जिलों में अपने खास ऑर्डर से सजा होता है। डीएनए की सिग्मेंट को जींस भी कहते हैं, जो शरीर में अलग–अलग रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि किस जींस का क्या काम होता है, इसके आधार पर फसल को जेनेटिक मॉडिफाई किया जाता है।

जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें देश के लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे दुनिया में तकरीबन एक अरब की आबादी का पेट भरता है? इस सवाल का जवाब देते हुए देश के कृषि के जानकार **शिवनंदनलाल** ने कहा कि विश्व में कोई भी ऐसा जीएम खाद्यान्न नहीं है जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। वास्तव में हमारी ज्यादातर जीएम फसलें उत्पादन क्षमता को कम करती हैं। अमेरिकी कृषि विभाग भी स्वीकार करता है कि जीएम कॉटन यानी मक्का और सोया की उत्पादकता सामान्य प्रजाति से भी कम है। दुनिया में खाद्यान्न की कमी नहीं है। समूची धरती पर लगभग 7.5 अरब लोग रहते हैं जबकि हम इतना अनाज पैदा कर लेते हैं कि उससे 12 अरब लोगों का पेट भर सकते हैं। यदि दुनिया की एक अरब से ज्यादा आबादी भूखी सोती है तो इसकी वजह खाद्यान्न की कमी नहीं, बल्कि इनका बेतरतीब वितरण है। लगभग यही स्थिति भारत में भी है। जहां की कुल जनसंख्या की एक–तिहाई आबादी बाजार में उपलब्ध होने पर भी अनाज खरीद नहीं पाती। यहां तक कि हमारे यहां की 80 करोड़ गरीब जनता सस्ते गल्ले की दुकान से भी राशन नहीं खरीद पाती। कोरोना काल में इन्हें मुफ्त राशन देना पड़ा था। सवाल उत्पादन का नहीं, सवाल उसकी अधिकता और वितरण का ज्यादा है।

जीएम फसलें किसानों पर कैसा विपरीत असर डालती हैं?

इस सवाल के जवाब में पूसा इंस्टिट्यूट के कृषि विज्ञानी **डॉ एस. आर. सिंह** ने कहा कि जैविक रूप से उत्पादित खाद्यान्न से भारी मात्रा में कचरा पैदा होता है, जिसे किसी रसायन से काबू में नहीं लाया जा सकता। गौरतलब है कि अमेरिका के जार्जिया सीमांत क्षेत्र में बड़ी तेजी से बंजर होने लगी थी। इसके पीछे रासायनिक कचरे को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। दुनिया के करीब 26 देशों की जमीन इसी तरह से जीएम फसलों के कारण बंजर होने के कगार पर पहुंच गई हैं। जीएम उत्पाद के बारे में माना जाता है कि इससे हमारे देश में पाए जाने वाले खाद्यानों की विविधता भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी भारत सरसों का पुराना और पारंपरिक उत्पादक देश रहा है। इस लिहाज से भी भारत को सरसों उत्पाद को लेकर ज्यादा सजग और सतर्क रहना ही होगा।

अमेरिका की ही बात करें तो खुद वहां इस तरह की फसलों के उत्पादन की मनाही है। इतना ही नहीं अन्य देशों में भी इस तरह के उत्पादन पर लगभग रोक है। इस बाबत कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि जब खाद्यान्न इंसानों के लिए सुरक्षित है तो फिर क्या वजह है कि लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में इस बाबत हुए रिसर्च दर्शाते हैं कि जीएम सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यहां तक कि मोनसेंटो कंपनी ने खुद यूरोप में चूहों पर किए गए अपने अध्ययनों में पाया कि उनके शरीर में कई अंग मसलन किडनी, लीवर, पाचन तंत्र, खून आदि में गंभीर जटिलताएं पाई गई। इतना ही नहीं उनमें एलर्जी की भी शिकायतें देखी गई। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जीएम खाद्यान्नों से प्रजनन क्षमता पर भी खासा असर पड़ा।

जहरीले रासायनिक पदार्थों के बल पर तैयार होने वाली इन जीएम फसलों से न तो भूमि का भला हो सकता है और न ही इन खाद्यान्नों को खाने वाले मनुष्यों का। इन फसलों से पैदा होने वाले खाद्यान्नों को खाकर इंसान की क्या दशा होगी इसकी कल्पना की जा सकती है।

नैनी एग्रीकल्चर इन्स्टीटयूट के अध्यापक **डॉ. आर.पी. सिंह** का कहना है कि बड़ी–बड़ी विदेशी कंपनियां पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को अपने मुट्ठी में करना चाहती हैं। वह हर हाल में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए वह हर तरह की तरकीब भी अपना सकती हैं। पूर्व में जिस तरह बीटी बैंगन को लेकर इन कंपनियों ने दबाव बनाया था, लग रहा था कि पूरा का पूरा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में है। जीएम सरसों का मामला भी उससे अलग नहीं है। सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आपस में मिली हुई है और हर हाल में उनकी नजर आम किसानों की जेब पर है।

हमारा देश प्राचीन काल से ही पारंपरिक खेती का देश रहा है। वर्तमान सरकार ऑर्गेनिक खेती पर जोर दे रही है। ऐसे में विदेशी कंपनियों के इशारे पर इस तरह की जहरीली खेती के लिए जगह बनाना, किसी रहस्य से कम नहीं है।

जीएम सरसों के मसले को जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय तक ले जाने वाली **पर्यावरणविद अरुणा**

रोड्रिग्स का कहना है कि सरकार एक तरफ तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती है, तो दूसरी तरफ इस प्रकार की नीतियां लाकर खेती में रसायनों के प्रभाव को बढ़ाती हैं। हमारे देश में कृषि कार्य में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी जुड़े हुए रसायनों के प्रयोग से कृषि कार्य में लगे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। अगर इसको नहीं रोका गया तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी खेती दिन प्रतिदिन और जहरीली होती जाएगी। मस्टर्ड बहुत छोटा बीज होता है। इसलिए इसके खराब या बर्बाद होने की आशंका ज्यादा रहती है लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि हम अन्य देशों के अनुभव से सबक लें। कनाडा में 90 फ़ीसदी किसानों की गेहूं की खेती बर्बाद हो गई। अमेरिका में भी परिणाम अच्छे नहीं रहे, तो भारत में अच्छे परिणाम कैसे हो सकते हैं? दबे पांव भारतीय बाजार में ग्लाइफोसेट ने जो जगह बना ली है, उससे होने वाले नुकसानों को तो हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इससे निपटना और मुश्किल हो जायेगा।

आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ **प्रो. अश्वनी महाजन** का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मायाजाल बढ़ता ही जा रहा है। हालिया विकसित किए गए डीएमएच–11 को स्वदेशी कह कर भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर इस जीएम फसल की मंजूरी सरकार द्वारा दी जाती है तो वह भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। देश में जीएम सरसों की व्यवसायिक खेती से सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनी बायर को फायदा होगा, क्योंकि जीएम सरसों की फसल को कीटनाशकों और खरपतवार से बचाने के लिए सिर्फ बायर कंपनी के कीटनाशक ही कारगर होंगे। जीएम फसलों पर सामान्य फसलों से कई गुना ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है। पहले ही फसलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां बढ़ी है। जीएम सरसों से बने खाद्य तेलों या सरसों के साग के साथ कीटनाशक के रूप में हम जहर खाने को मजबूर हो जाएंगे।

डॉ. महाजन ने कहा कि हमारे देश में सरसों की अन्य किस्में हैं जो जीएम सरसों की तुलना में ज्यादा उत्पादन दे सकती हैं। यही कारण है कि भारत अभी कुछ साल पहले तक खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर देश था। आज हम 60 प्रतिशत से ज्यादा खाद्य तेल आयात करने लगे हैं। देश में तिलहन उत्पादन किसानों के लिए फायदेमंद नहीं रह गया है। यह सब अनायास हुआ या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धोखे में। यह समय ऐसे सवालों का जवाब तलाशने का है, न कि भारत की भूमि पर जीएम फसलों का बोझ लादने का। भारत में जीएम सरसों की अनुमति देने से खाद्य तेल का आयात तो नहीं घटेगा, लेकिन हर तरह के खाद्यान्नों का निर्यात जरूर कम हो जाएगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

जीएम फसलः छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान तो नहीं !

मिस्र के शर्म अल शेख शहर में 6 से 18 नवंबर 2022 तक दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती को बचाने के उपायों पर मंथन करेंगे। कोप–27 के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा होगी। जलवायु परिवर्तन को ठीक करने का वैश्विक प्रयास सिर्फ धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी लाने तक सीमित नहीं है। इसमें तितली, चील, सरीसृपों और विलुप्त होते कीट–पतंगों को बचाने पर भी जोर है। यह कभी हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अहम घटक थे, लेकिन मिट्टी, पानी, हवा और खाद्य श्रृंखला में हुई छेड़छाड़ से हर सप्ताह एक जीव या पादप प्रजाति विलुप्त हो रही है।

देश में इन दिनों आनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मोडिफाइड) सरसों के जरिए प्रकृति और विज्ञान की सरहद पर बहस छिड़ी है। पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाले बायोटेक रेगुलेटर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) ने जीएम सरसों के बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति दी है। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा तय मानकों के अधीन धरा मस्टर्ड हाइब्रिड (डीएमएच–11) पर परीक्षण होंगे। इससे देश में जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती का रास्ता खुलेगा। यदि ऐसा होता है तो डीएमएच–11 देश की पहली जीएम खाद्य फसल होगी। 2017 में जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती की सिफारिश की गई थी, लेकिन उस समय पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर और शोध की जरुरत बताकर रोक लगा दी थी। हालांकि जीएम कपास, तेल आज भी खुले बाजार में बिक रहा है। वह हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो चुका है। बीटी (बेसिलस थुरिनजेनिसस) कपास की खेती को 2002 में मंजूरी दी गई थी।

जीएम फसलों के लुभावने आंकड़ों के बावजूद हमें इसे खाद्य श्रृंखला में शामिल करने से पहले जरुरत, विकल्प और नियामकीय पहलुओं पर विचार करना होगा। बीज की आनुवांशिकी में बदलाव का कोई भी प्रयास जैव विविधता, मानवीय सेहत और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना होगा।

–अरविंद कुमार मिश्रा

फसलों की इंजीनियरिंग

जीएम फसलों में पादप कोशिकाओं के डीएनए (जीनोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट) में कुछ इस तरह बदलाव किए जाते हैं कि वह कुछ खास खरपतवारों (हर्बिसाइट) और रोग को लेकर प्रतिरोधी बन जाती हैं। इसका उद्देश्य परंपरागत बीज से अधिक उत्पादकता और

पोषक तत्व हासिल करना है। जीएम फसलों के पैरोकारों का दावा है कि जीएम फसलों में ऊर्वरक और पानी का उपयोग कम होगा। यही नहीं आनुवांशिक अभियांत्रिकी से तैयार ये फसलें मौसम में आ रहे अप्रत्याशित बदलावों में भी अच्छी पैदावार देती हैं। जेनेटिक मोडिफिकेशन के अलावा आनुवांशिक रूप पृथक दो प्रजातियों की उप प्रजातियों के बीच संकरण (हाइब्रिडाइजेशन) से भी नई किस्म तैयार की जाती है, लेकिन सरसों के मामलें में यह संभव नहीं है। इसकी वजह इसका स्वयं परागण (सेल्फ पॉलिनेटिंग) गुण है। यही वजह है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा जीन में बदलाव कर सरसों की एक नई स्वदेशी प्रजाति विकसित की गई है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में एक जीन स्थापित किया गया है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी पहचान तय करने के लिए हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन डाला गया है। लेकिन इसको लेकर बायो सेफ्टी परीक्षण हुए हैं या नहीं और उनका स्तर क्या है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

तेजी से बढ़ रहा जीएम फसलों का रकबा

जीएम फसलों की बुआई 1994 में सबसे पहले अमेरिका में हुई। टमाटर की एक प्रजाति (फ्लेवर सेवर) के रूप में इसका विकास किया गया था। टमाटर की इस प्रजाति को लेकर दावा किया गया था कि यह पकने में अधिक समय लेने के साथ जल्द खराब नहीं होगा। ब्रिटेन की साइंस एकेडमी द रॉयल सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका आलू, लौकी, कद्दू, सोयाबानी और चुकंदर, बांग्लादेश– बैगन, चीन– पपीता, भारत समेत 15 से अधिक देश कपास एवं 17 देशों में मक्का का उत्पादन जीएम प्रजाति से हो रहा है। रकबे के अनुपात में चीन, अमेरिका और अर्जेंटिना जीएम फसलों पर सबसे अधिक निर्भर हैं। 2015 में 28 देशों में लगभग 18 करोड़ हेक्यटेयर में जीएम फसलों की खेती होने लगी थी। 2016 तक यह कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10 प्रतिशत है। आज सोयाबीन के कुल वैश्विक उत्पादन का 60 प्रतिशत जीएम प्रजाति पर निर्भर है। यूएस नेशनल सेंटर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक आनुवंशिक रूप से कपास के परिणामस्वरूप 50 लाख एकड़ में 85 मिलियन पाउंड फसल की पैदावार बढ़ी। लेकिन जितने बड़े रकबे में इसकी खेती की जा रही है, उस लिहाज से उत्पादन में यह अप्रत्याशित वृद्धि नहीं कही जाएगी।

आयात निर्भरता कम होने का दावा

जीएम सरसों की ओर कदम बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत की खाद्य तेलों पर विदेशी निर्भरता कम करना है। हम लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपये की राशि हर साल खाद्य तेलों के आयात पर खर्च करते हैं। वनस्पति तेल की अपनी 70 प्रतिशत जरुरत के लिए हम मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, अर्जेंटिना, रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं। आयातित सोयाबीन तेल का बड़ा अनुपात जीएम श्रेणी का है।

भारतीय विकल्पों पर बढ़ने की जरुरत

सिर्फ दो दशक पहले की ही बात करें तो देश में सरसों की फसलों में किसी तरह की खाद और उर्वरक की जरुरत नहीं पड़ती थी। भारतीय किसान अपनी जरुरत के लिए सरसों की फसल एकल रूप में या फिर गेंहूं के साथ बुआई कर उसकी पैदावार करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में धान और गेंहू पर ज्यादा निर्भरता ने तिलहन, दलहन और मोटे अनाज को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। सवाल यह है कि क्या हमारे पास जीएम फसलों के अलावा तिलहन की पैदावार बढ़ाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देश को खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की। देश में खाद्य तेल के आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी लगभग 56 प्रतिशत है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू खाद्य और पाम ऑयल के राष्ट्रीय मिशन (एनएमईओ–ओपी) से किसान पाम और तिलहन की खेती में वृद्धि के लिए प्रेरित हुए हैं। तिहलन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर लागत प्रदान करने की नीति को भी अपनाया है। पिछले दो साल में केंद्र सरकार के प्रयासों से तिलहन उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है। 2017–18 में तिलहन का उत्पादन 314. 59 लाख टन रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले तीन साल में तिलहन फसलों में उत्पादकता 1.271 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर (2018–19) से बढ़ाकर 1.292 किलोग्राम/हेक्टेयर कर दी गई है। हालांकि वैश्विक औसत अब भी दो हजार किग्रा प्रति हेक्येटयर है। इस अंतर की बड़ी वजह हमारे यहां तिलहन का कम होता रकबा भी है। पिछले साल 191.75 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुआई हुई, इससे पहले यह 193. 28 लाख हेक्टयेर था। देश में मूंगफली और सोयाबीन की बुआई का रकबा तेजी से घटा है। सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित विकल्पों को ही एकमात्र विकल्प बताया जा रहा है, जबकि तिलहन का रकबा 103 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इसमें सबसे अधिक वृद्धि सरसों में देखी गई है। पिछले वर्ष तो सरसों का भाव खुले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपये प्रति क्विंटल से भी अधिक रहा. हालही में केंद्र सरकार

ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है.तिलहन उत्पादन 2014–15 में 27.51 मिलियन टन से बढ़कर 2021–22 में 37.70 मिलियन टन पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित होने वाली फसलों में सरसों, मूंगफली, तिल को भी शामिल किया गया है। वैज्ञानिकों का एक धड़ा इस तथ्य को भी स्वीकार्य करता है कि जीएम सरसों के अलावा भी देश में अधिक पैदावार देने वाली सरसों की कई प्रजातिया हैं। तिलहन और दलहन आत्मनिर्भरता के सामने एक बड़ी चुनौती गेंहूं और धान को जरुरत से ज्यादा वरीयता देना भी है। कृषि अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जितना पैसा खाद्य तेलों के आयात मोर्चे पर खर्च हो रहा है, उसे तिहलन किसानों को फसल की कीमत के रूप में देने की रणनीति अच्छे परिणाम देगी।

दूर करनी होंगी पर्यावरणीय और स्वास्थ्य चिंताएं

संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को आज की जरुरत बताया है, लेकिन उन्होंने इसके परीक्षण और नियामक की कमजोर व्यवस्था पर भी चेताया है। जीएम फसलों के लिए जिस तरह ग्लाइफोसेट जैसे शाकनाशकों (हर्बिसाइट) का इस्तेमाल बढ़ा है, उसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जताई है। 2015 में डब्ल्यूएचओ ने ग्लाइफोसेट को संभावित कैंसरजनक के रूप में वर्गीकृत किया था।

एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 85 प्रतिशत से अधिक जीएम फसलें हर्बिसाइड टॉलरेंट (शाकनाशक प्रतिरोधी) हैं। इससे भले ही तात्कालिक रूप से कुछ सालों तक फसलों की उच्च पैदावार हासिल कर ली जाए, लेकिन इंसानी सेहत के साथ ही पर्यावरण पर दीर्घकालिक नुकसान का आकलन भी होना चाहिए।

अमेरिका समेत कई देशों के अनुभव बताते हैं कि जीएम फसलों का रकबा बढ़ने से ग्लाइफोसेट प्रतिरोधी हर्बिसाइड में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वह खेत जो कभी अच्छी पैदावार के लिए जाने जाते थे, आज व्यापक रूप से खरपतवार से मुक्ति का संघर्ष कर रहे हैं। भारत में जहां पहले ही जोत का आकार छोटा और आबादी का दबाव अधिक है, यह संकट को और बढ़ा सकता है।

उत्साहजनक नहीं बीटी कपास का अनुभव

2002 में बीटी कॉटन के आनुवांशिक रूप से संशोधित बीज के उपयोग कोमंजूरी मिली थी। देश आज कपास का दुनिया भर में सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके पीछे बीटी कपास को श्रेय दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीटी कपास पारंपरिक कपास के मुकाबले 24 प्रतिशत अधिक उपज देता है। इससे किसानों की आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में बीटी कपास की खेती करने वाले किसानों ने ऊर्वरक का उपयोग बढ़ने के साथ ही बीटी कपास में नई प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की शिकायत की है। बीटी कॉटन को जिस पिंक बॉलवर्म (गुलाबी सुंड़ियों) से प्रतिरोधक माना गया था, वह फिर इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। 2012 में कृषि संबंधी संसदीय समिति जीव–जंतुओं पर बीटी कॉटन के प्रतिकूल असर पर चिंता जाहिर कर चुकी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसके बीजों को जब मेमनों को खिलाया गया तो उनके यकृत, हृदय, गूर्दे, फेफड़ों और अमाशय के वजन में कमी आ गई। महज कुछ सालों में बीटी कॉटन किसान न सिर्फ पहले जैसी स्थिति में खड़े हैं बल्कि उस जमीन की ऊर्वरक शक्ति में भी काफी कमी आई है।

अमेरिका और यूरोप में उठे विरोध के स्वर

इसमें कोई दो मत नहीं कि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक आबादी जिस तरह बढ़ी है, उसके लिए खाद्यान संकट को दूर करने में जीएम फसलों ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जीएम फसलों को लेकर चिंताएं भी कम नहीं हैं। अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप मेंजीएम खाद्य पदार्थों के खिलाफ हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन इसकी बानगी हैं। इनमें कुछ देशों में नागरिकों द्वारा पूरी तरह जीएम फसलों पर प्रतिबंध की मांग हो रही है। कुछ साल पहले तक अमेरिका और यूरोपीय देशों में जीएम और गैर जीएम खाद्य पदार्थ में अंतर नहीं किया जाता था। अब उनसे जुड़े नियामक तय कर दिए गए हैं। जीएम और गैर जीएम खाद्य पदार्थों के लिए अलग–अलग मानक चिन्ह हैं। जीएम फसलों के विरोध का स्वर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार से भी जुड़ा है। अमेरिकी कंपनी मोंसेंटो अकेले जीएम बीज की वैश्विक बिक्री में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।

जीएम फसलों के लुभावने आंकड़ों के बावजूद हमें इसे खाद्य श्रृंखला में शामिल करने से पहले जरुरत, विकल्प और नियामकीय पहलुओं पर विचार करना होगा। बीज की आनुवांशिकी में बदलाव का कोई भी प्रयास जैव विविधता, मानवीय सेहत और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना होगा। वह भी तब जब धरती गंभीर जलवायु संकट से गुजर रही है। ऐसी परिस्थितियों में आज भारत पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में न सिर्फ नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है, बल्कि विकास की जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए जैविक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व जगत को राह दिखा रहा है।❑❑

लेखक जी–न्यूज के मुख्य प्रतिलिपि संपादक हैं।

स्वावलम्बन का आधार स्वदेशी

आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में व्यवहार किये जाते हैं किन्तु इन्हें एक दूसरे का पूरक भी समझा जा सकता है। इसका व्यष्टिगत और समष्टिगत संदर्भ अलग–अलग है। इसका तात्पर्य यह है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी आत्मनिर्भर हों और सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोज़गार हो, भले ही नौकरी न हो और उसकी आय का एक ऐसा स्तर हो जिससे वह अपने स्वाभिमान और अस्मिता को बचाने में सक्षम हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और उसे इतना भोजन और आवास प्राप्त हो जिससे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में वह अपना निर्वाह कर सके। स्वस्थ रहने का अर्थ है, स्व में स्थित रहना और यही स्वदेशी का तात्त्विक अर्थ भी है।

समाज परस्परावलंबन और पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही चल सकता है। कोई व्यक्ति अनाज उत्पन्न करता है, कोई शिक्षा देता है, कोई घर बनाता है और इस प्रकार परस्परावलंबन के आधार पर अलग–अलग गुण और कर्म पर आधारित समाज सर्वांगीण विकास की दिशा में तीव्र गति से एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। स्वावलंबन और परस्परावलंबन एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं और आपसी सहयोग और योग्यता के आधार पर हम एक आदर्श गाँव या ज़िले की अवधारणा तैयार कर सकते हैं।

परावलंबन अलग हैं और यह नहीं होना चाहिये

आज अगर हम विदेशी वस्तुओं का और विदेशी पूँजी तथा विदेशी तकनीक पर निर्भर रहेंगे तो परावलम्बी बने रहेंगे। अतः हमें स्वदेशी को ही अपनाना होगा। हमने स्वदेशी संकल्प के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का निश्चय किया है। हमारा लक्ष्य, अर्थव्यवस्था को ग्राम आधारित और रोज़गार आधारित एक विकेंद्रित प्रणाली के द्वारा ग़रीबी का उन्मूलन करते हुए धर्म और संस्कृति पर आधारित स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण करना है। पिछले तीस वर्षों से चली आ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो तथाकथित सुधारवादी आर्थिक नीतियाँ चल रही हैं, इनसे हमारा देशीय संचय घटा है और विदेशी पूँजी का वर्चस्व बढ़ा है। हमारा घरेलू उद्योग कमजोर हुआ है। सिर्फ़ कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो सके हैं। ग़रीबी और बेरोज़गारी का स्तर बढा है। आर्थिक विषमता बढ़ी है। हमें व्यवस्था और नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। स्वदेशी तत्वज्ञान को आचरण में ढालने की आवश्यकता है।

प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और उसे रहने के लिए घर के साथ इतना भोजन प्राप्त हो जिससे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में वह अपना निर्वाह कर सके। स्वस्थ रहने का अर्थ है, स्व में स्थित रहना और यही स्वदेशी का तात्त्विक अर्थ भी है।

– ड़ा. धनपत राम अग्रवाल

स्वधर्म के आधार पर मनुष्य के गुण और कर्म का अलग–अलग होना एक स्वाभाविक क्रिया है और वर्णाश्रम व्यवस्था भी इसी आधार पर बनी है। अर्थ व्यवस्था के तीन विभाग भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया के ही अंग हैं और तदनुसार कृषि, उद्योग तथा सेवा के विभिन्न क्षेत्र सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में समन्वय तथा परस्पर सहयोग के साथ विकास के पथ की दिशा पर चलते हैं। आज आर्थिक नीतियों के दोष के कारण कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग गरीब हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कृषक और गावों को स्वावलंबी कैसे बनाया जाये।

आत्मनिर्भरता स्वाभिमान की रक्षा का एक लक्ष्य है। हम अपने प्राकृतिक तथा अन्य पूँजीगत एवं मानव संसाधनों के उचित विनियोजन द्वारा उनका संयमित दोहन करते हुए हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। परन्तु दोहन की जगह अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं तो पर्यावरण की समस्या पैदा

होती है और मानव संसाधन का शोषण करते हैं तो समाज की समरसता घटती है। आर्थिक विषमता समाज के लिये अभिशाप है। किसानों की फसल का उचित मूल्य और श्रम का उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिये। आत्मनिर्भरता की यही कुंजी है। अगर हमारा किसान और मज़दूर आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होता है तो उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि होती है और देश के उद्योग आगे बढ़ सकते हैं। इससे सरकार की सब्सिडी का खर्च घट सकता है, जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य तथा देश की सुरक्षा में खर्च किया जा सकता है। स्वावलंबन के लिये कुटीर तथा लघु उद्योग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इसके लिये उनको सस्ते ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था तथा आधुनिक तकनीक की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये। सबसे महत्वपूर्ण बात है उनके उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था और यहाँ स्वदेशी भावना का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतियोगात्मकता को वरीयता मिलनी चाहिये। उपभोक्ताओं के बीच स्वदेशी जीवन पद्धति के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी आवश्यक है।यहाँ यह समझना भी ज़रूरी है कि अर्थ व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये कुछ सामग्रियों का आयात देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना अनिवार्य होता है। जैसे पेट्रोल, डीज़ल के लिये कच्चा तेल हमें अरब देशों से आयात करना पड़ता है और कुछ आधुनिक तकनीक से बनी मशीनों एवं कुछ दवाइयों को भी अनिवार्य रूप से आयात करना पड़ता है। इसके अलावा और बहुत सारे उपभोग के सामानों का आयात होता है जिन्हें स्वदेशी तकनीक को और अधिक विकसित करके स्वावलंबी होने की आवश्यकता है। इसके लिये हमारे अनुसंधान क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें निजी औद्योगिक क्षेत्र को ज़िम्मेवारी लेनी चाहिये क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का तीन चौथाई से ज़्यादा हिस्सा निजी क्षेत्र से ही आता है जब कि अनुसंधान का तीन चौथाई से ज़्यादा हिस्सा सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। आज का युग बौद्धिक सम्पदा पर आधारित है। अमेरिका और यूरोप की कुल आय का एक तिहाई से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ़ पैटेंट और कापी राइट की रॉयल्टीज़ से आ जाता है जो कि हमारी कुल राष्ट्रीय आय के दोगुना से भी अधिक है। यह मानसिक बदलाव लाना बहुत आवश्यक है और हमारी प्रज्ञा को बाहर जाने से रोकने में भी मदद मिलेगी। इसका दूरगामी और दीर्घकालीन प्रभाव हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने और हमारे स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने में मिलेगा। धीरे–धीरे मोटर गाड़ी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे और हमारा न सिर्फ़ आयात घटेगा बल्कि हम अपना निर्यात भी बढ़ा सकेंगे। हमारे मानव संसाधन की मर्यादा बढ़ेगी और बौद्धिक सम्पदा में हम अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकेंगे। अभी हम तकनीक का आयात करते हैं, फिर हम इसका निर्यात करेंगे। अभी हम व्यापार घाटे की स्थिति में हैं और इसकी भरपाई विदेशी ऋण और विदेशी पूँजी से करते हैं, जिसका बोझ बढ़कर 1.5 ट्रिलियन यूएस डालर से भी ज़्यादा हमारे देश पर है। विदेशी पूँजी के मुख्यतः तीन श्रोत हैं – विदेशी ऋण, शेयर बाज़ार में निवेश तथा उद्योग या सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश (एफडीआई)। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार होते हुए भी चालू वित्त वर्ष में लगभग 100 बिलियन यूएस डालर का आयात चीन से हुआ है और निर्यात सिर्फ़ 25 बिलियन यूएस डालर और फलतः व्यापार घाटा 75 बिलियन यूएस डालर के लगभग हुआ है। इसकी उल्टी गिनती चालू करने की आवश्यकता है, तभी हमारा रुपया अमेरिकन डालर की तुलना में मज़बूत हो सकेगा। स्वावलम्बन और आत्मनिर्भर भारत की पहचान तभी हो सकेगी जब भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपना स्थान बना सकेगा और अपनी क्रय क्षमता के अनुकूल अपनी क़ीमत बना सकेगा जो कि आज के दिन लगभग सिर्फ़ 15 रुपये होने के बावजूद बाज़ार मूल्य 83 रुपये का है। रुपये की दर में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि और बढ़ती हुई मँहगाई है, जिसके मूल में रुस–यूक्रेन युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक–राजनैतिक अस्थिरता है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज दर में लगातार बढ़ोतरी का मुख्य कारण वहाँ की 7–8 प्रतिशत की महंगाई है, जिसकी वजह से हमारे रिज़र्व बैंक ने भी ब्याज दर को बढ़ाया है। रूपये की दर में गिरावट को रोकने के उपाय किये जा रहे हैं और विदेशी व्यापार भी अधिकांश देशों के साथ डालर में नहीं करके रूपये में करने की कोशिश की जा रही है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी पिछले एक साल में लगभग 100 बिलियन यूएस डालर घटा। ऐसे गंभीर हालातों में देशी संचय क्षमता को बनाये रखना ज़रूरी है ताकि पूँजी के विनियोजन और रोज़गार सृजन के लिये हमें विदेशी पूँजी पर आश्रित नहीं होना पड़े। स्वदेशी और स्वावलम्बन ही एकमात्र विकल्प है जो हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारी आर्थिक क्षमता को एक प्रखर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करा सकता है।

उपरोक्त भूमिका को ध्यान में रखकर ही हमें आज के युगानुकूल चिंतन करने की आवश्यकता है। तकनीक और ज्ञान–विज्ञान के आज के युग में व्यावहारिक चिंतन आवश्यक है। हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता सर्वोपरि है। ❑❑

(लेखक स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक हैं।)

आक्रामक चीन और भारत के हित

सन् 1976 के बाद यह पहला मौका है जब शी जिनपिंग को असाधारण तौर पर एक बार फिर पार्टी की कमान सौंपी गई है। जिनपिंग चीन के संस्थापक माओ से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। बीजिंग के ग्रेट हाल में अपने खास लोगों से बातचीत करते हुए जिनपिंग ने, हालांकि भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वह भारत की चिंता बढ़ाने वाली है। चाहे पीएलए को वर्ल्ड क्लास सेना बनाने का मामला हो या परमाणु हथियार का जखीरा बढ़ाने का। स्थानीय युद्ध में जीत का जिक्र कर उन्होंने भारत के साथ–साथ ताइवान के साथ जारी सीमा विवाद को रेखांकित कर यह संकेत दे दिया है कि चीन की रणनीति भारत के हित के विपरीत होगी। ऐसे में भारत को भी चीन का सामना आने वाले कुछ वर्षों तक करने के लिए खुद को तैयार करना ही होगा।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बीसवीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद जिनपिंग का पार्टी सेना और पूरे राज्य पर पूर्ण नियंत्रण लगभग हो गया है। जाहिर तौर पर तमाम मूलभूत परिवर्तन देखें जा रहे हैं। देंग शियाओपिंग के जमाने से चली आ रही वैश्विक खिलाड़ियों सहित निजी पूंजी के माध्यम से धन सृजन के मामले में भी नीतिगत मोड़ आएगा। अब राज्य की बड़ी भूमिका होगी, केंद्रीय नियोजन अधिक होगा और धन के केंद्रीकरण के स्थान पर साझी समृद्धि की खोज होगी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो नए कार्यकाल में राज्य और निजी पूंजी के संबंधों में आमूलचूल बदलाव होंगे।

शून्य कोविड़ नीति के परिणामस्वरुप चीन का आर्थिक विकास धीमा हो गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार एक स्पष्ट संकेत भेज रही है कि अब राज्य आर्थिक एजेंटों को निर्देशित करेगा। इससे पहले चीन ने लगभग 3 दशकों तक उच्च आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अब वह अमेरिका के अधिपत्य और श्रेष्ठता को सीधे चुनौती देना चाहता है। राजनीतिक तटस्थता का यह दृष्टिकोण व्यापार और निवेश प्रवाह को काफी हद तक बदल सकता है। ऐसे में हमें अपने हितों की रक्षा करनी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन ने इसे भांपते हुए प्रौद्योगिकियों और विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में भारी संघीय निवेश को बढ़ावा देने की मांग की है। जिन क्षेत्रों में चीन अभी हावी है वहां अमेरिका निवेश को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रहा है। एप्पल और

उभरता हुआ चीन भारत के लिए एक दुर्जेय विरोधी बना हुआ है, हमें कई मोर्चों पर खुद को तैयार करने की जरूरत है।

– के.के. श्रीवास्तव

टेस्ला जैसी कंपनियों की असहमति के बावजूद अमेरिका ने चीन के चिप आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत को भी अपने सामरिक और आर्थिक हितों की रक्षा करनी होगी। हम चीनी सैन्य और आर्थिक शक्ति की सम्मिलित शक्ति को देखते हुए अपने पड़ोसी का विरोध नहीं उठा सकते और न ही हम उसके सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। वर्तमान की स्थिति दुलमूल है। चीन के साथ व्यापार कम करने के तमाम घोषणाओं के बावजूद 2020–21 में भारत में चीनी आयात 90 अरब डॉलर से अधिक का हुआ था। भारत को फार्मास्यूटिकल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जिसके लिए चीन तीन सक्रिय अवयवों की आपूर्ति करता है।

अपने मार्गदर्शक सिद्धांत ''प्रत्येक से उनकी क्षमताओं के अनुसार और प्रत्येक को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार'' के आदर्शों वाला चीन अब पुराना कम्युनिस्ट देश नहीं रहा। चीन की चाल, उसका चरित्र और चिंतन बदल चुका है। सत्तारूढ़ दल ने रियल्टी क्रेडिट और फिनटेक क्षेत्रों को स्पष्ट संदेश दिया है। आर्थिक रणनीतिकारों के साथ उनकी लगातार चर्चा हो रही है। मालूम कि 2002 से 2012 के बीच हूं चिंताओं के जमाने में वहां की अर्थव्यवस्था 10.5 प्रतिशत की गति से बढ़ी थी लेकिन 2012 से 2021 के दरमियान घटकर 6.5 प्रतिशत ही रह गई है। शी कालस्य अगले दशक में चीन को मध्य स्तर का विकसित देश बनाना है, इसके लिए इसे लगभग 5 प्रतिशत वार्षिक दर की आवश्यकता है। लेकिन घटती जनसंख्या, घटती उत्पादकता वृद्धि और भारी कर्ज के बोझ जैसी प्रतिकूलता के कारण इसके 2.5 प्रतिशत की दर से ही बढ़ने का अनुमान है। संपूर्ण विश्व और विशेष रुप से भारत के लिए इसके कई निहितार्थ हैं। फिर भी चीन के निकट भविष्य में दुनिया की

शी की सरकार फिलहाल अपनी फाल्ट लाइनों को ठीक करने में जुटी हुई है। वहां से आ रहे संकेत सहज बता रहे हैं कि चीन भारत का दुश्मन बना रहेगा।

सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि अमेरिका अपना ओहदा बचाए रखने के लिए आगे भी प्रयास जारी रखेंगा। इससे इतर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के माध्यम से चीन अपनी ऋण संचालित प्रगति का लक्ष्य वैश्विक प्रभुत्व के विस्तार के लिए बनाया है। लेकिन कर्जदार देश श्रीलंका के तरह की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं तो उसकी हेकड़ी निकल सकती है और उसके लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है।

हालांकि शी ने चीन को आक्रामक संसोधन वादी विश्व नेता देश के रूप में पेश करने की कोशिश की है लेकिन असल में वह विश्व व्यवस्था को अपने हिसाब से आकार देना चाहता है और चीन से तय किए गए निर्णयों के आधार पर दुनिया को चलाना चाहता है। हालांकि यह सब अभी भी दूर की कौड़ी है। ऐसे में जबकि चीन की अर्थव्यवस्था की गति धीमी है प्रतिकूल जनासांख्यिकी के कारण श्रम शक्ति घट रही है। वहां की एक बड़ी आबादी धीरे–धीरे बूढ़ी हो रही है। ऐसे में एक बारगी निजी पूंजी से धन सृजन पर रोक लगा कर दुनिया पर राज करने का सपना उसके लिए दिवा स्वप्न जैसा ही है।

फिर भी विचारणीय प्रश्न है कि उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अमेरिका के सामने क्या चीन नवाचार तकनीक का महाशक्ति बना रहेगा। जहां तक भारत का संबंध है तो भारत को चीन के साथ शांति मिलने की संभावना न के बराबर है। इसलिए इसका एक मात्र उपाय है कि भारत अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे, चीन पर निर्भरता कम करे समान विचारधारा वाले देशों के साथ अपने हितों को संरेखित करे और अपने रक्षा तैयारियों को उन्नत करें।

शी की सरकार फिलहाल अपनी फाल्ट लाइनों को ठीक करने में जुटी हुई है। वहां से आ रहे संकेत सहज बता रहे हैं कि चीन भारत का दुश्मन बना रहेगा। चीन से निपटने के लिए तथा भारतीय हितों के खिलाफ मिल रही चुनौतियों को कुंद करने के लिए नई दिल्ली को कड़ी मेहनत करनी होगी तथा कामों में अपेक्षाकृत तेजी लानी पड़ेगी। शी ने साझा नियति के नाम पर शख्स राजनीतिक नियंत्रण आर्थिक विकास के लिए बाजारों के खिलाफ राज्य की बढ़ती निर्भरता और विदेशों में अधिक मुखर नीतियों को फायलानए का फैसला किया है निश्चित रूप से यह व्यक्ति वादी सता का विरोधाभास जैसा है जिसकी कलई कभी भी खुल सकती है। लेकिन नई दिल्ली को उससे निपटने के लिए सेना के साथ तैयारी करनी होगी। एक सशक्त सेना के साथ शत्रुता पर आमादा चीन के खिलाफ खड़ा होना होगा। शी के नेतृत्व में चीन की सरकार ने अपने विस्तृत भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा को कभी भी ओझल नहीं होने दिया है इसे देखते हुए भी कहा जा सकता है कि भारत चीन के संबंधों के मधुर होने के आसार नहीं है। दरअसल हमें कैसे विरोधी का सामना कर रहे हैं जिसके पास दुनिया को देखने की एक श्रेणीबद्ध दृष्टि है उसे हम दुनिया की भागीदारी और अपनी उच्च राष्ट्रीय शक्ति के जरिए ही पीछे छोड़ सकते हैं। ❑❑

गर्भपात का अधिकारः कानूनी दांव पेच से आगे

हाल ही में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले से एकल, अविवाहित महिलाओं के साथ–साथ वैवाहिक बलात्कार की शिकार महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के दायरे में लाया गया है, जिससे उनके लिए गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल सुनिश्चित हुई है। निःसंदेह यह एक प्रशंसनीय फैसला है लेकिन आगे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि महिलाओं को वास्तविक व्यवहार में इसका लाभ मिल सके। विवाहित और अविवाहित का भेद मिटाते हुए न्यायालय ने सभी महिलाओं के व्यक्तिगत स्वायत्तता गरिमा और निजता के अधिकारों को जरूरी बताया है। इसी तरह हालांकि वैवाहिक बलात्कार को अभी तक भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के रूप में मान्यता नहीं है लेकिन अदालत ने महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी पर यौन हमला बलात्कार हो सकता है। भारतीय उच्च न्यायालय का यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका की अदालतों की तुलना में अत्यधिक प्रगतिशील और जीवंत है। मालूम हो इसी साल जून के महीने में अमेरिकी अदालत ने गर्भपात से संबंधित प्रतिगामी कानून पारित किए तथा गर्भपात के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया था।

भारतीय महिलाओं को 1971 से ही गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, रोज विकसित हो रहे विज्ञान की पृष्ठभूमि में इस कानून को 2021 में अद्यतन किया गया था। फिर भी पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक कलंक के कारण महिलाओं को खासकर अविवाहित महिलाओं को कानून से प्राप्त अधिकार का प्रयोग करने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देश में आज भी 60 से 70 प्रतिशत गर्भपात के मामले स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के बाहर ही होते हैं। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक प्रतिवर्ष लगभग 16 मिलियन गर्भपात में से 12 मिलियन गर्भपात स्वास्थ्य सुविधा के बाहर किए जाते हैं। इनमें भी अधिकांश केस शल्य चिकित्सा के बगैर गोलियों के माध्यम से किए जाते हैं। आमतौर पर यह दवाई पुरुषों द्वारा महिलाओं को दी जाती हैं। अधिकांश महिलाओं के पास सुरक्षित और प्रत्यक्ष स्वास्थ्य देख–रेख, सलाह और समर्थन की पहुंच नहीं है। 8 से 10 प्रतिशत तक सर्जरी अयोग्य लोगों द्वारा की जाती है। यही सब कारण है कि देश में प्रतिवर्ष

कानून से प्राप्त कवच निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमें इसके आगे की यात्रा की जरूरत है।
– डॉ. जया कक्कड़

असुरक्षित और अधूरे गर्भपात के कारण 8 प्रतिशत मातृ मृत्यु होती है, ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी बदतर है।

ऐसे में एक व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत विकल्पों का प्रयोग करने के लिए एक महिला की निर्णयात्मक स्वायत्तता के लिए अदालत की ओर से आई यह मान्यता देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ 4078 मामले दर्ज किए गए थे, वास्तविक आंकड़ा और अधिक हो सकता है।

सभी भारतीय महिलाओं को प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा गर्भपात की आवश्यकता है। गैर शल्य चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के जरिए गर्भपात की जानकारी के साथ–साथ इस बारे में उन्हें मार्गदर्शन और समर्थन की भी जरूरत है, लेकिन यह सिर्फ एक मेडिकल मामला नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा भी है। इसलिए सामाजिक सुधार की भी जरूरत है। कानून को लागू करना आवश्यक है लेकिन समाज को साथ लिए बगैर वास्तविक कार्यान्वयन संभव नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर की एक महिला की याचिका पर महिलाओं की स्वायत्तता को स्पष्ट किया है। महिला ने रिलेशनशिप के टूट जाने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति चाही थी। अदालत ने इस मान्यता के साथ फैसला दिया कि कानून को समय के साथ विकसित होना चाहिए। महिला विवाहित हो या अविवाहित यदि यौन रूप से सक्रिय है तो उसके पास गर्भपात करने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं के पास सामाजिक मानदंडों और मूल्यों से प्रभावित हुए बिना गर्भ निरोधक, बच्चों की संख्या या गर्भपात के बारे में निर्णय लेने का विवेकाधिकार होना चाहिए।

वर्ष 2015 में आई लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना 16 मिलियन गर्भपात होते हैं इसका मतलब है कि 8 से 10 मिलियन महिलाओं को स्वास्थ्य के खतरों का सामना करना पड़ता है।

अदालत ने अंतरंग साथी हिंसा की संभावना और सहमति से संबंध में गैर सहमति वाले यौन संबंध की संभावना को भी स्वीकार किया है। विवाह नामक संस्था की रक्षा के नाम पर पुरुषों द्वारा जबरदस्ती छोड़ देने और एक गलत संस्कृति में भी यौन हिंसा को समझने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार या निर्धारित किया गया था कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है। इस आधार पर जिन महिलाओं ने यौन उत्पीड़न करने वाले पतियों के वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ संघर्ष किया, वे सब इस फैसले से अपने को सही और राहत महसूस कर रही हैं।

हालांकि वर्तमान में वैवाहिक बलात्कार को आईपीसी की धारा 375 के अपराधों के तहत बलात्कार की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने इस पर सुनवाई हो रही है लेकिन अभी तक इसे संज्ञेय अपराध नहीं बनाया गया है। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का सुझाव है, कि यदि किसी महिला को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समान रूप से स्वायत्तता और गरिमा की गारंटी दी जाती है तो वैवाहिक बलात्कार को संज्ञेय अपराध कहा जाना चहिए। ज्ञात हो कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने सिफारिश की थी, यौन उल्लंघन के खिलाफ बचाव के रूप में वैवाहिक संबंधों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

पुनः फैसले में कहा गया है प्रजनन अधिकारों का दायरा महिलाओं के बच्चा पैदा करने या ना करने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है। प्रजनन अधिकारों में वास्तव में गर्भनिरोधक और जन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षण, और जानकारी तक पहुंचने का अधिकार, यह तय करने का अधिकार कि क्या और किस प्रकार के गर्भनिरोधको का प्रयोग करना है, या चुनने का अधिकार कि क्या और कब और कितने बच्चा पैदा करने का अधिकार आदि सब शामिल है।

बेहतर स्वास्थ्य ढांचा के साथ उचित देखभाल की बात अदालत ने की थी लेकिन दूसरा पक्ष यह है देश में प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के लगभग 80 प्रतिशत पद रिक्त हैं कुछ गिनती के धनाढ्य लोग महंगी निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधा पा लेते हैं। लेकिन 55 प्रतिशत से अधिक गरीब लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती। वर्ष 2015 में आई लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना 16 मिलियन गर्भपात होते हैं इसका मतलब है कि 8 से 10 मिलियन महिलाओं को स्वास्थ्य के खतरों का सामना करना पड़ता है।

कानून से प्राप्त कवच निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन हमें इसके आगे की यात्रा की जरूरत है। हमें देखभाल की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है ताकि गर्भपात सेवाएं मांग पर सुलभ हो और गरीबों तथा वंचितों के लिए मुफ्त हो। साथ ही साथ पुरुष प्रधान भारतीय समाज की मानसिकता में बदलाव के लिए जागरूकता फैलाई जाए ताकि महिला के अधिकार के प्रति व्यवहार वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और करुणामय हो। ❑❑

भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का हाल

भारत की अर्थव्यवस्था एक ओर दुनिया की ऊपरी पायदान पर चढ़ रही है तो दूसरी ओर भारत सभी दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की कोशिश में है। इसका मतलब हरगिज यह नहीं है कि भारत के प्रश्न कम हुए है या सब कुछ कुशल मंगल है। भारत में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' और 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' ऐसी दो योजनाएँ है जो चलने का मतलब ही यह है कि भारत अब भी पिछड़ा हुआ है और इसकी अर्थव्यवस्था अपने बहुत सारे लोगों को रोजगार देने एवं उनको सही आय स्त्रोत देने में समर्थ नहीं है। लेकिन यह भी सराहनीय है कि भारत ऐसी योजना चला रहा है जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रतीक है। एक योजना में 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज देने की बात है तो दूसरी में हर काम कर सकने वाले ग्रामीण वयस्क को मांगने पर रोजगार देने की। यह दुनिया की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाएँ मानी जाती है। अनाज योजना के लिए भारत के पास अनाज का भंडार काफी है, इसलिए यह योजना चलाने में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। लेकिन रोजगार गारंटी योजना चलाना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसको पैसा लगता है और नए–नए काम की योजनाएं भी चलानी पड़ती है और यही चिंता का विषय है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

सूखे की स्थिति में मददगार हो, ऐसे रोजगार निर्माण की बात तो कौटिल्य के जमाने से भारतीय सोच में रही है और वैसे प्रयत्न भी होते रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिश शासक भारत को सभी दृष्टि से कंगाल करके गए और जनता खाने–खाने को मोहताज हुई तो ऐसी योजना की जरूरत ज्यादा महसूस हुई और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रोजगार अवसर निर्माण करने हेतु बहुत सारे कदम उठाए। लेकिन रोजगार निर्माण के सही प्रयत्न 1970 के दशक से शुरू हुए, जिससे ग्रामीण स्वयं रोजगार या प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्माण पर ज़ोर दिया गया। महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने ऐसी रोजगार गारंटी योजना

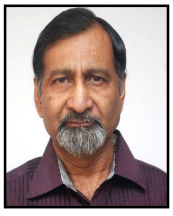

सर्वांगीण ग्रामीण आत्मनिर्भरता से भरे विकास से ही गरीब को आय का स्त्रोत तथा बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता है। अभी इस ओर ज्यादा प्रयत्न की आवश्यकता है।

– अनिल जवलेकर

1972–73 के सूखे की परिस्थिति में सहायता हेतु शुरू की। जिसको बाद में राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारा गया। पहले 1977 में काम के लिए अनाज और बाद में 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए रोजगार गारंटी की बात हुई। सन् 2000 आते–आते जवाहर रोजगार योजना के नाम से एक योजना आयी। ऐसे कई रास्ते से गुजरते हुए और कई नाम से अमल में होते हुए आखिरकार कानूनन रोजगार गारंटी की बात की गई और ऐसा कानून 2005 में पास किया गया। तब से जम्मू और कश्मीर छोड़ देश भर में यह योजना लागू है।

यह योजना रोजगार देने की गारंटी देती है

जाहिर है कि यह रोजगार योजना ग्रामीण वयस्कों के लिए बनाई गई ताकि उन्हें अपने गांव या उसके आसपास रोजगार मिले और उन्हें काम ढूंढने के लिए दूर शहर में न जाना पड़े। इसलिए यह योजना हर ग्रामीण घर के वयस्क को जो अकुशल काम करने को तैयार है, कम से कम वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की व्यवस्था करती है। ग्रामीण महिलाओं को भी यह योजना लागू है और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ग्राम सभा तथा राज्य सरकार को इसमें विशेष भूमिका है। इस योजना के खर्चे में केंद्र सरकार प्रशासन का खर्च, मजदूरी तथा तीन चौथाई सामग्री का खर्च देती है। बाकी खर्चे राज्य सरकार उठाती है। इस योजना में काम के लिए विस्तृत रचना की गई है और सभी प्रकार के विकास योग्य काम शामिल किए गए है। मजदूरी का दर केंद्र सरकार तय करती है और 15 दिन के अंदर मजदूरी देने का प्रावधान है। अगर किसी कारणवश रोजगार नहीं दे सके तो रोजगार भत्ता देने की बात भी इस योजना में है।

गारंटी रोजगार योजना सफल मानी जाएगी

इसमें दो राय नहीं है कि भारत में ग्रामीण रोजगार निर्माण की जरूरत थी और है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था कृषि पर आधारित है और कृषि ही सबसे बड़ा रोजगार निर्माण का साधन था। लेकिन यह बात समझी गई कि कृषि में जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे है और उनको कृषि से निकालकर किसी और क्षेत्र में रोजगार देने से गरीब की आर्थिक हालत सुधर सकती है। इसलिए 70 दशक से स्वयं रोजगार देने एवं कुछ को प्रत्यक्ष रोजगार देने की बात की गई। ऋण व्यवस्था को सरल किया गया और बेरोजगार को ऋण कम ब्याज और अनुकूल किश्तों पर मिले इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। ऋण सब्सिडी भी दी गई। लेकिन यह काफी नहीं था। प्रत्यक्ष रोजगार देना भी जरूरी था और रोजगार गारंटी योजना ने यह काम सफलतापूर्वक किया।

निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है की रोजगार गारंटी योजना काफी हद तक सफल हुई है। आज भी 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना पर काम कर रहे है और यही इसकी उपलब्धि कही जा सकती है। कोरोना काल में यह योजना गरीब बेरोजगारों के लिए उपयुक्त रही, यह भी सामने आया है। इस योजना की पहचान इससे होती है कि ग्रामीण लोग चाहते है कि हर बेरोजगार को इस योजना पर काम मिले, न कि सिर्फ हर घर–परिवार से एक को।

योजना की कमियां पर ध्यान देना भी जरूरी

ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी बड़ी योजना जो भारत देश जैसे विशाल देश में लागू की गई हो उसमें कुछ कमियां न मिले। हाल ही में अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में इस योजना की उपयुक्तता पर अभ्यास किया और पाया कि यह योजना ग्रामीण विभाग में सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही थी। जो त्रुटियाँ पाई गई उसमें मुख्यतौर पर यह भी पाया गया कि 39 प्रतिशत रोजगार कार्डधारकों को रोजगार नहीं मिल पाया तथा कुछ को 100 दिन के बदले सिर्फ 64 दिन ही रोजगार मिल सका तथा मजदूरी भी समय पर नहीं मिली। अभ्यास में यह भी देखा गया कि योजना में बजट की कमी है और इसे बढ़ाना होगा। मजदूरी दर की कमी भी इस योजना की समस्या है। ठेकेदारी से काम करवाने को मनाई के बावजूद कुछ जगह पर उनको देखा गया। सभी त्रुटियों पर गौर करना जरूरी है।

ग्रामीण आत्मनिर्भरता भरा विकास जरूरी

निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि गरीबी पर मुफ्त अनाज देने की और रोजगार निर्माण के लिए बेरोजगार को सरकारी गारंटी देकर काम देना कोई दीर्घकालीन इलाज नहीं है।

आज का विकास मॉडल नैसर्गिक संसाधनों के शोषण पर आधारित है और शहरी विकास और शहरी जीवन पद्धति पर ज़ोर देता है, जो रोजगार बढ़ाने में नाकामयाब रहा है। इसलिए ग्रामीण रोजगार योजना गत 50 वर्षों से चलाने की बाद भी समस्या वहीं की वहीं है। अकुशल रोजगार के काम से हटकर अब कुशल रोजगार के काम भी इसमें शामिल करना जरूरी है ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर के बड़े काम भी इस योजना के जरिये हो सके। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सर्वांगीण ग्रामीण आत्मनिर्भरता से भरे विकास से ही गरीब को आय का स्त्रोत तथा बेरोजगार को रोजगार दिया जा सकता है। अभी इस ओर ज्यादा प्रयत्न की आवश्यकता है। ❑❑

खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुकसान को रोकना आज की आवश्यकता

इस पृथ्वी पर रहने वाले मानवों की भलाई के लिए खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुकसान को रोका जाना आज की आवश्यकता बन गया है। पूरे विश्व में ही आज खाद्य पदार्थों की बर्बादी बड़े स्तर पर हो रही है। इससे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा पर भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यूनाइटेड नेशन्स के पर्यावरण कार्यक्रम के एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 14 प्रतिशत खाद्य पदार्थों का नुक्सान खाद्य पदार्थों को उत्पत्ति स्थल से खुदरा बिक्री स्थल तक पहुंचाने में हो जाता है। इसके अलावा, अन्य 17 प्रतिशत खाद्य पदार्थों का नुक्सान इन्हें खुदरा बिक्री स्थल से उपभोक्ता के स्थल तक पहुंचाने में हो जाता है। खाद्य पदार्थों के इतने बड़े नुक्सान का वातावरण में उत्सर्जित हो रही कुल गैसों में 8 से 10 प्रतिशत तक का योगदान रहता है। आज खाद्य पदार्थों में इस भारी मात्रा में हो रहे नुक्सान का असर पूरे विश्व में रह रहे मानवों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर बहुत विपरीत रूप से पड़ रहा है एवं खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में लगातार हो रही कमी के चलते ही विश्व के सभी देशों में मुद्रा स्फीति की समस्या भी खड़ी हो गई है।

खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुक्सान की समस्या दिनों दिन बहुत गंभीर होती जा रही है। यह केवल खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुक्सान से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि इन पदार्थों के उत्पादन पर खर्च किये जाने वाले समय, पानी, खाद, श्रम, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु लागत एवं अन्य स्त्रोतों के अपव्यय का गंभीर विषय भी शामिल है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के होने वाले अपव्यय एवं नुक्सान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में खर्च होने वाले डीजल, पेट्रोल का भी न केवल अपव्यय होता है बल्कि वातावरण में एमिशन गैस को फैलाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाली आपूर्ति चैन एवं इन खाद्य पदार्थों के कुल जीवन चक्र पर भी विपरीत असर पड़ता है। कुल मिलाकर खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुक्सान से सभी देशों पर ही हर प्रकार से बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

यदि आवश्यकता के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का उत्पादन होने लगे और खाद्य पदार्थों के नुक्सान एवं अपव्यय को पूर्णतः रोक लिया जाये तो देश को होने वाले आर्थिक नुक्सान को कम करने के साथ ही वातावरण में उत्सर्जन (गैसों) की मात्रा भी कम की जा सकती है।
–स्वदेशी संवाद

वर्ष 2014 में किए गए एक अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुक्सान से देश को भारी आर्थिक हानि भी होती है। इस प्रतिवेदन के अनुसार भारत को वर्ष 2014 में इस मद पर 92,156 करोड़ रुपए का आर्थिक नुक्सान हुआ था। न केवल खाद्य सामग्री के उत्पादन तक बल्कि खाद्य सामग्री के उत्पादन के बाद भी भारी नुक्सान होते हुए देखा गया है। भारत में इस नुक्सान का आंकलन वर्ष 1968 से किया जा रहा है एवं इस नुक्सान को नयंत्रित करने के प्रयास भी निरंतर किए जा रहे हैं परंतु उचित परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। विशेष रूप से उत्पादन के बाद के नुक्सान को समाप्त करने के लिए आज सम्पूर्ण सप्लाई चैन को ही ठीक करने की जरूरत है। उचित स्तर पर अधोसंरचना के विकसित न होने के चलते भी अक्सर सब्ज़ियों एवं फलों का अधिक नुक्सान होते देखा गया है।

140 करोड़ नागरिकों की जनसंख्या वाले भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के खाद्य पदार्थों का नुकसान, बहुत भारी नुकसान है, जो देश की आर्थिक प्रगति को भी सीधे सीधे ही प्रभावित कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार यदि खाद्य पदार्थों के इस नुकसान को रोक दिया जाय तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी उच्छाल लाया जा सकता है एवं इससे अंततः नागरिकों की आय में वृद्धि हो सकती है।

खाद्य पदार्थों का अपव्यय एवं नुक्सान विभिन स्तरों पर होता है। सबसे पहले तो किसान द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलों की बुआई के समय से ही खाद्य पदार्थों का अपव्यय एवं नुक्सान प्रारम्भ हो जाता है। फिर फसल के पकने के बाद फसल की कटाई करने से लेकर फसल के उत्पाद को मंडी में पहुंचाने तक भी खाद्य पदार्थों का अपव्यय

140 करोड़ नागरिकों की जनसंख्या वाले भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के खाद्य पदार्थों का नुकसान, बहुत भारी नुकसान है, जो देश की आर्थिक प्रगति को भी सीधे सीधे ही प्रभावित कर रहा है।

एवं नुक्सान होता है। मंडी से खुदरा व्यापारी तक उत्पाद को पहुंचाने पर भी नुक्सान होता है। इसके बाद खुदरा व्यापारी से खाद्य पदार्थों को उपभोक्ता तक पहुंचाने में भी नुक्सान होता है। हालांकि इस पूरी चैन में कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों में नुक्सान होने देना नहीं चाहता है परंतु फिर भी इसे रोक पाने में असमर्थता सी महसूस की जा रही है।

खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुक्सान को रोकने हेतु अधोसंरचना को विकसित करने एवं सप्लाई चैन का अर्थपूर्ण उपयोग करने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। कोल्ड स्टोरेज हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित किए जा रहे हैं परंतु यह अभी भी इनकी लगातार बढ़ रही मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे है। दूसरे, कोल्ड स्टोरेज को ग्रामीण इलाकों में भी स्थापित किए जाने की आज आवश्यकता है। नागरिकों को खाद्य पदार्थों के अपव्यय एवं नुक्सान से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुक्सान की जानकारी देकर उनमें इस सम्बंध में पर्याप्त जागरूकता लाने की भी जरूरत है। कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के साथ ही इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए अच्छे रेल एवं रोड मार्ग के साथ ही यातायात की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होना भी बहुत जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में ही फुड प्रॉसेसिंग इकाईयों की स्थापना भी की जानी चाहिए ताकि खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े अथवा कम आवश्यकता पड़े।

कभी–कभी आवश्यकता से अधिक पैदावार होने से भी किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आवश्यकता से अधिक पैदावार हो जाने से इन पदार्थों की कीमतें बाजार में बहुत कम हो जाती हैं जैसे, आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के बारे में अक्सर देखा गया है। जिसके चलते किसान को बहुत नुक्सान होता है और वह इन फसलों को बर्बाद करने में ही अपनी भलाई समझता है। इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए एवं विभिन्न पदार्थों के उत्पादन की सीमा तय की जा सकती है ताकि देश में किस पदार्थ की जितनी आवश्यकता है उतना ही उत्पादन हो। और, इस प्रकार की फसलों की बर्बादी को रोका जा सके। कब, कैसे, कहां, कितनी मात्रा में किस फसल का उत्पादन देश में किया जाना चाहिए, इस पर गम्भीरता से आज विचार किये जाने की आवश्यकता है। ताकि, विभिन्न पदार्थों के अपव्यय एवं नुक्सान पर अंकुश लगाया जा सके।

खाद पदार्थों के नुक्सान का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे उत्सर्जन (गैसों) के बढ़ने के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि आवश्यकता के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का उत्पादन होने लगे और खाद्य पदार्थों के नुक्सान एवं अपव्यय को पूर्णतः रोक लिया जाये तो देश को होने वाले आर्थिक नुक्सान को कम करने के साथ ही वातावरण में उत्सर्जन (गैसों) की मात्रा भी कम की जा सकती है।❑❑

ऐतिहासिक करवट के प्रतीक ऋषि सुनक

भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होना, कई अर्थों में ऐतिहासिक घटना है। ब्रिटेन गर्व करता है कि उसके उदार लोकतंत्र में किसी भी रंग और धर्म का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। दूसरी और भारत को भी गर्व है कि उसके मूल का एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है जो 75 साल पहले तक भारत का शासक था। गुलामी के सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को तहस–नहस करने वाले देश ब्रिटेन में सुनक की ताजपोशी वहां की बिगड़ चुकी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के गरज से की गई है। यही तो हमारा आदर्श है, यही तो हमारी सभ्यता है, यही तो हमारी संस्कृति है और यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम का नारा है।

इतिहास पर नजर रखने वाले जानते हैं कि एक समय में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों की नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता का उपहास उड़ाया था। लेकिन आज उसी ब्रिटेन के प्रशासन की डोर भारतीय मूल के एक राजनेता के हाथ में आ चुकी है। सुनक से पहले भी कई भारतवंशी विभिन्न देशों के शासन अध्यक्ष बन चुके हैं लेकिन ब्रिटेन जैसे देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का व्यक्ति पहली बार बना है। यह भारतीयों की प्रतिभा के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाती है।

भारतवंशी अपनी प्रतिभा और समर्पण के बदौलत हर दिशा और हर विधा में धीरे–धीरे छाते जा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2008 में छपे इक्नामिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध विमानकी और अंतरिक्ष संस्था नासा में 36 प्रतिशत वैज्ञानिक और अमेरिकन एसोसिएशन आफ फिजिशियंस आफ इंडियन ओरिजिन के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के लगभग 30 प्रतिशत चिकित्सक भारतीय मूल के हैं। कमोबेश यही स्थिति व्यवसाय में भी है। भारतीय व्यवसायियों द्वारा स्थापित किए जा रहे व्यवसाय लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विश्व की बड़ी कंपनियां भी भारतीय मूल के पेशेवरों को सर्वोच्च पदों पर नियुक्त कर रही है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली में नियुक्त इंजीनियरों में एक तिहाई से अधिक भारत से हैं। पूरी दुनिया में लगभग 10 फ़ीसदी उच्च तकनीकी कंपनियों के

ऋषि सुनक सिर्फ भारतीय मूल से संबंध नहीं रखते, बल्कि भारत की सनातन परंपरा इनकी व्यवहारिकता में भी शामिल है। ब्रिटेन के सबसे उच्च पद के लिए भी अपने संस्कारों से समझौता न कर अपने स्पष्ट इरादों को दुनिया के समक्ष उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

सीईओ भारतीय मूल के हैं। और तो और राजनीति के क्षेत्र में भी 10 विभिन्न देशों में कुल 31 बार भारतीय मूल के व्यक्ति प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हैं।

भारतीय मूल के विश्व प्रसिद्ध उद्योगपतियों में आर्सेलर मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, जेडी स्केलर, के. जय चौधरी, माइक्रोसिस्टम के पूर्व संस्थापक विनोद खोसला, वेदांता रिसोर्सेज के अनिल अग्रवाल, सिंफनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक रोमेश वाधवानी, जैसे तमाम नाम शामिल है। आज हजारों की संख्या में अप्रवासी भारतीय विदेशों में अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। दुनिया भर के देशों में भारतीय उद्योगपतियों की लिस्ट तो लंबी हो ही रही है, उनकी नेटवर्थ और बाजार मूल्यांकन में भी तेजी देखी जा रही है। उदाहरण के तौर पर विनोद खोसला की नेटवर्थ 2020 के 2.3 अरब अमेरिकी डालर से 2 वर्ष में बढ़कर 5.3 अरब अमेरिकी डालर तक पहुंच गई है। वहीं रमेश वाधवानी की कुल संपत्ति 2020 के 3. 4 अरब डालर के मुकाबले बढ़कर 5.1 डालर हो गई है। आईटी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसाफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भारतीय मूल के हैं। प्रसिद्ध इंटरनेट कंपनी अल्फाबेट के सुंदर पिचाई भी भारतीय मूल के हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी एजेब के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्ण, एल.एम. वेयर के रंगराजन रघुराम, स्टार नेटवर्क की जयश्री, मास्टरकार्ड के अजय पाल सिंह बग्गा सहित अनेक भारतीय मूल के पेशेवर न सिर्फ लोकप्रिय हैं, बल्कि बहुत ही सही ढंग से आईटी और तकनीकी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। पहले भारतीय पेशेवरों को तकनीकी व्यवसाय तक सीमित माना जाता था लेकिन बार्कलेज केसीएस वेंकट आदि विभिन्न क्षेत्र में भारतीय मूल के पेशेवरों का प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। कहने का आशय है कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय मेधा का वर्चस्व लगातार विस्तृत हो रहा है।

गुलामी प्रथा के अंत होने के बाद ब्रिटेन को श्रमिकों की जरूरत पड़ी। जिसके बाद भारत से मजदूर बाहर के देशों में जाने लगे। भारत के बाहर जाने वाला प्रत्येक भारतीय अपने साथ एक छोटा भारत लेकर ही जाता है। भारतवंशी अपने साथ तुलसी का रामचरित्रमानस, भाषा, खानपान एवं परंपराओं के रूप में भारतीय संस्कृति को लादे हुए ही घूमता हैं।

फिर से लौट कर आते हैं ऋषि सुनक पर। सबको मालूम है कि ब्रिटेन आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। लंदन में काबिल और मजबूत इरादों वाला व्यक्ति चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह मानक स्थापित किया है कि आधुनिक समय में एक विचारशील प्राणी जिसके अंदर इच्छाशक्ति हो, किसी भी देश की परंपरा को आधार बना, इसकी मौलिकता को कायम रखते हुए, आर्थिक सुधार को लाकर, अपने राष्ट्र को सही पटरी पर ला सकता है। ब्रिटेन ने ऋषि सुनक में जायज तौर पर यही सब खोजा होगा।

ऋषि सुनक सिर्फ भारतीय मूल से संबंध नहीं रखते, बल्कि भारत की सनातन परंपरा इनकी व्यवहारिकता में भी शामिल है। ब्रिटेन के सबसे उच्च पद के लिए भी अपने संस्कारों से समझौता न कर अपने स्पष्ट इरादों को दुनिया के समक्ष उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था। ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड में हुआ किंतु इन्हें, परिवार में भारत के पंजाब में पैदा हुए दादा और पिता की परवरिश मिली। भारत में पैदा हुई, पली–बढ़ी अक्षता का संग मिला। दो बेटियां हैं और दोनों का नामकरण शुद्ध हिंदी शब्दों पर आधारित है। घर की जीवन पद्धति सनातन और भारतीय विचारों से संबद्ध रही है।

दरअसल गुलामी प्रथा के अंत होने के बाद ब्रिटेन को श्रमिकों की जरूरत पड़ी। जिसके बाद भारत से मजदूर बाहर के देशों में जाने लगे। भारत के बाहर जाने वाला प्रत्येक भारतीय अपने साथ एक छोटा भारत लेकर ही जाता है। भारतवंशी अपने साथ तुलसी का रामचरित्रमानस, भाषा, खानपान एवं परंपराओं के रूप में भारतीय संस्कृति को लादे हुए ही घूमता हैं। यही कारण है कि फीजी, त्रिनिडाड, गुयाना सूरीनाम और मारीशस लघु भारत के रूप में उभरे।

इस फेहरिस्त में बहुत सारे नामों को गिनाया जा सकता है, खैर ऋषि सुनक का ग्रेट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत और भारतवंशियों के लिए निश्चित ही गर्व की बात है। भारत से बाहर बसा हर एक भारतवंशी भारत का ब्रांड अंबेसडर होता है। इनकी सफलता से भारत का गर्व होना लाजमी भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो सिलसिला छेदी जगन ने शुरू किया और जिसे मारीशस में शिवसागर, रामगुलाम से लेकर अनिरुद्ध, जगन्नाथ, वासुदेव पांडे, चंद्रिका प्रसाद संतोषी, कमला हैरिस और अब ब्रिटेन में सुनक ने आगे बढ़ाया है, वह आगे भी निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और भारतवंशी भारत के बाहर भी बड़े–बड़े पदों पर आसीन होते रहेंगे। ❑❑

विकसित देशों की तुलना में भारत में तेजी से कम हो रही है गरीबी

विकसित देशों के कुछ अर्थशास्त्रियों ने भारत के विरुद्ध जैसे एक अभियान ही चला रखा है और भारत के आर्थिक विकास को वे पचा नहीं पा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अप्रैल–जून 2022 तिमाही में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है और वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने जा रहा है। इस प्रकार भारत न केवल आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है बल्कि भारत आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। परंतु, फिर भी इन अर्थशास्त्रियों द्वारा मानव विकास सूचकांक में भारत को श्रीलंका से भी नीचे बताया जाना, आश्चर्य का विषय है। यह विरोधाभास इन अर्थशास्त्रियों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि श्रीलंका की हालत तो जग जाहिर है एवं आर्थिक दृष्टि से भारत एवं श्रीलंका की तुलना ही नहीं की जा सकती है। आर्थिक विकास के साथ मानव विकास भी जुड़ा है। भारत में आर्थिक विकास तो तेज गति से हो रहा है परंतु इन अर्थशास्त्रियों की नजर में भारत में मानव विकास में लगातार गिरावट आ रही है। यह एक सोचनीय विषय है।

विकसित देशों के अर्थशास्त्री मानव विकास सूचकांक को आंकते समय न केवल भारत के आर्थिक विकास को पूर्णतः नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि भारत में तेजी से कम हो रही गरीबी एवं आर्थिक असमानता पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

–प्रहलाद सबनानी

अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक (एचडीआर) प्रतिवेदन 2021–22 जारी किया है। एचडीआर की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2020 में 130वें पायदान पर था और 2021 में 132वें पर आ गया है, ऐसा इस प्रतिवेदन में बताया गया है। मानव विकास सूचकांक का आंकलन जीने की औसत उम्र, पढ़ाई, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। कोरोना महामारी के खंडकाल में भारत का इस सूचकांक में निचले स्तर पर आना कोई हैरान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। परंतु, वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के बीच भारत को एचडीआर रैंकिंग में लगातार नीचे जाता हुआ दिखाया जा रहा है। जबकि, इसी अवधि में चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, भूटान और मालदीव जैसे देशों की रैंकिंग ऊपर जाती हुई दिखाई जा रही है। श्रीलंका, बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे देशों की आर्थिक स्थिति के बारे आज हम अनभिज्ञ नहीं है।

इसी प्रकार इन अर्थशास्त्रियों द्वारा भारत में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इनके अनुसार, भारत के 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए से भी कम कमाते हैं। भारत की जनसंख्या यदि 140 करोड़ मानी जाय तो देश की कुल जनसंख्या के 16.42 प्रतिशत नागरिक 375 रुपए से कम कमा रहे हैं, जबकि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में इस सम्बंध में जारी किए गए आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओ में आज भारत के ऊपर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी आते है। अगर इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गरीबी के आकंडें देखे तो कई चौकाने वाले खुलासे सामने आते है।

सबसे पहले अगर अमेरिका की बात की जाय तो अमेरिका की कुल आबादी के 11.4 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि अमेरिका को विश्व का सबसे अमीर एवं विकसित देश माना जाता है। चीन के सम्बंध में तो कोई वास्तविक आंकड़े सामने आते ही नही है, अतः चीन की बात करना ठीक नहीं होगा। जर्मनी में भी स्थिति अमेरिका जैसी ही है। कुल आबादी में से 15.5 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जापान के सम्बंध में वर्ष 2020 में आई एक खबर के अनुसार जापान में गरीबों की संख्या बढ़ रही है एवं मध्यमवर्गीय लोगों की संख्या कम हो रही है। जापान में 15. 7 प्रतिशत नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

यह भी एक चौकाने वाली बात है कि विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में अमेरिका में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी उक्त चार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में सबसे कम आत्महत्याएं होती है। यह भी मानव विकास सूचनांक का एक अवयव है, परंतु मानव विकास सूचकांक में भारत की लगातार गिरती स्थिति ही दर्शाई जाती है।

अब भारत की बात करते हैं। भारत में वर्ष 1947 में 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, जबकि अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी जो आज बढ़कर लगभग 136 करोड़ हो गई है।

अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर (शोध पत्र) जारी किया है। इस शोध पत्र के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच भारत में गरीबों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 22.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019 में घटकर 10.2 प्रतिशत पर नीचे आ गई है अर्थात गरीबों की संख्या में 12.3 प्रतिशत की गिरावट दृष्टिगोचर है। अत्यंत चौंकाने वाला एक तथ्य यह भी उभरकर सामने आया है कि भारत के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या बहुत तेज गति से कम हुई है। जहां ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या वर्ष 2011 के 26.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 11.6 प्रतिशत पर आ गई है अर्थात यह 14.7 प्रतिशत से कम हुई है तो शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 7.9 प्रतिशत से कम हुई है।

उक्त शोधपत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी बताया गया है कि वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच गरीबों की संख्या अधिक तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से वर्ष 2015 के दौरान गरीबों की संख्या 3.4 प्रतिशत से घटी है वहीं वर्ष 2015 से 2019 के दौरान यह 9.1 प्रतिशत से कम हुई है और यह वर्ष 2015 के 19.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 10 प्रतिशत पर नीचे आ गई है। वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 के दौरान तो गरीबी 3.2 प्रतिशत से कम हुई है यह कमी पिछले दो दशकों के दौरान सबसे तेज गति से गिरने की दर है।

ग्रामीण इलाकों में छोटे जोत वाले किसानों की आय में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छी रही है जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या वर्ष 2015 के 21.9 प्रतिशत से वर्ष 2019 में घटकर 11.6 प्रतिशत पर नीचे आ गई है, इस प्रकार इसमें 10. 3 प्रतिशत की आकर्षक गिरावट दर्ज की गई है। उक्त शोधपत्र में यह भी बताया गया है कि बहुत छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में 2013 और 2019 के बीच वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है वहीं अधिक बड़ी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष दर्ज हुई है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने तो अपनी एक अन्य रिपोर्ट में भारत द्वारा कोरोना महामारी के दौरान लिए गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा है कि विशेष रूप से गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) को लागू किए जाने के चलते ही भारत में अत्यधिक गरीबी का स्तर इतना नीचे आ सका है और अब भारत में असमानता का स्तर पिछले 40 वर्षों के दौरान के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ज्ञातव्य हो कि भारत में मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है एवं इस योजना की अवधि को अभी हाल ही में दिसम्बर 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया है। उक्त मुफ्त अनाज, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत काफी सस्ती दरों पर (दो/तीन रुपए प्रति किलो) उपलब्ध कराए जा रहे अनाज के अतिरिक्त है।

इस प्रकार, विकसित देशों के अर्थशास्त्री मानव विकास सूचकांक को आंकते समय न केवल भारत के आर्थिक विकास को पूर्णतः नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि भारत में तेजी से कम हो रही गरीबी एवं आर्थिक असमानता पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी भी देश में यदि आर्थिक विकास होकर गरीबों की संख्या में कमी आएगी तो स्वाभाविक रूप से उस देश के नागरिकों का भी विकास होगा ही। ❑❑

प्रहलाद सबनानीः सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर (म.प्र.)

विदेशी मीडिया में भारत विरोधः कारण और निवारण

बहुत समय से विदेशी मीडिया में भारत का विरोध हो रहा है। यह विरोध धर्म, जाति और समाज व्यवस्था, पर्यावरण के नाम पर, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन, हिजाब जैसे कितने ही मुद्दों पर देखने को मिला हैं। पिछले आठ वर्षों में भारत आर्थिक शक्ति के रूप में दसवें स्थान से पांचवें स्थान पर पहुँच गया। भारत में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सामरिक शक्ति के रूप में भारत अमेरिका, रूस, चीन के सामने महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ है और आयुध शक्ति में आत्मनिर्भर होने लगा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण ने भारत की राजनीति की जीवन धारा मोड़ दी है। अयोध्या, काशी और उज्जैन के वैभव ने विश्व भर में बसे हिंदुओं का भारत में विश्वास और आस्था जाग चुका है। भारत में अपने अतीत के प्रति गौरव, धर्म और संस्कृति के प्रति गहरा विश्वास जाग्रत हो चुका है। कोरोना महामारी के कालखंड में जहां अमेरिका और चीन सहित सभी देशों की अर्थ व्यवस्थाएं अधोगति को प्राप्त हो रहीं हैं, वहाँ भारत लगातार सुदृढ़ स्थिति में है। अब हमारे उद्योग को विदेशी ऋण की आवश्यकता नहीं है और लगातार कॉर्पोरेट जगत में विदेशी ऋण की मांग घटी है। भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ऋणी नहीं है। बस यही बातें विदेशी मीडिया और समाचार पत्रों में भारत विरोधी अनर्गल प्रलाप का कारण है। इसके पीछे यह भी मंशा है कि भारत में विदेशी निवेश न हो और भारत के उत्पादों पर विश्वसनीयता कम की जाए। अधिकतर यह विरोध यूरोपीय और इस्लामिक देश, अमेरिका, चीन से प्रायोजित होते हैं। इनमें वैश्विक संगठन, विदेशी सरकारें, निजी स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ, निजी स्वार्थों द्वारा संचालित थिंक टेंक, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, सोशल मीडिया सम्मिलित होते हैं। दुख की बात यह है कि पश्चिमी मीडिया के इस कुलीनतंत्र में कुछ भारतीय और भारतीय मूल के टिप्पणीकार भी शामिल हैं। जिन भारतीयों को भारत के उत्थान से परेशानी है, वे पश्चिमी मीडिया में लिखते हैं, ताकि भारत की छवि पर लगातार आघात हो।

भारत विरोधी प्रचार वैश्विक भुखमरी सूचकांक, मीडिया स्वतन्त्रता, पर्यावरण, को लेकर अमर्यादित और अमान्य आंकड़ों के साथ किया जाता है। इस विदेशी दुष्प्रचार का कोई नियम, कानून नहीं है।

– विनोद जौहरी

कोरोना काल में भी हमने इसका भयंकर रूप देखा था जब भारत की स्वास्थ्य तंत्र, मेडिकल सुविधाओं, चिकित्सा प्रणाली को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विपरीत टिप्पणियाँ की थीं। भारत विरोधी प्रचार वैश्विक भुखमरी सूचकांक, मीडिया स्वतन्त्रता, पर्यावरण, को लेकर अमर्यादित और अमान्य आंकड़ों के साथ किया जाता है। इस विदेशी दुष्प्रचार का कोई नियम, कानून नहीं है और राजनयिक स्तर पर कोई समाधान नहीं होता। दुष्प्रचार के नए नए आयाम, संस्थाएं और श्रोत उत्पन्न होते रहते हैं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं होती।

इस विदेशी भारत विरोधी प्रचार के आधार पर भारत में भी निजी स्वार्थों, राजनीतिक अजेंडे, विघटनकारी और सांप्रदायिक तत्वों द्वारा देश में भ्रामक और विद्वेषात्मक प्रचार किया जाता है। एक पुस्तक (पोलिटिक्स आफटर टेलीविजनः हिन्दू नेशनेलिज्म एंड दा रेशपिंग आफ दा पब्लिक इन इंडिया) में तो दूरदर्शन चैनल पर रामानन्द सागर के सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण को प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की आलोचना भी की थी। फ्रांस स्थित एक संस्था आरएसएफ़ द्वारा 180 देशों में भारत को जनवरी 2022 में 150 वें स्थान पर रखा गया है जबकि हमारे देश में ही खुलकर सभी टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और सोशल मीडिया सरकार, हिन्दू धर्म और संस्कृति की आलोचना करते हैं। विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत को 121 देशों में 107 वें स्थान पर रखा गया है जबकि इस वर्ष भारत से 50 बिलियन अमेरिकी डालर के खाद्यान निर्यात हुआ हैं और हमारा देश कृषि में आत्मनिर्भर है। विदेशी मीडिया में भारत के विरुद्ध नकारात्मक समाचार अधिक प्रचारित होते हैं। चीन का ग्लोबल टाइम्स भारत के विरुद्ध लगातार दुष्प्रचार करता रहता है और भारत में गरीबी पर तंज़ कसता रहता है।

कश्मीर हमारे देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में है, लेकिन न्यूयहर्क टाइम्स में कश्मीर के बारे में जब भी खबरें छपती हैं तो उनमें मोदी और भारतीय सेना को खलनायक की तरह पेश किया जाता है ...

बीते दिनों अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नौकरी का एक अनोखा विज्ञापन दिया। वह भारत समेत दक्षिण एशिया क्षेत्र में बिजनेस संवाददाता की नियुक्ति के लिए ऐसे पत्रकार को ढूंढ रहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए। चाहे नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक मामले हों, पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक हो, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो, नागरिकता संशोधन कानून लाना हो, या कोरोना महामारी से निपटना और विश्व की सहायता करना हो, इन सबको न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके सम्बद्ध मीडिया संस्थानों ने असफल, विनाशकारी और आत्मघाती ही घोषित किया।

न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर पर मोदी और भारतीय सेना को खलनायक की तरह पेश किया जाता है। कश्मीर हमारे देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में कश्मीर के बारे में जब भी खबरें छपती हैं तो उनमें मोदी और भारतीय सेना को खलनायक की तरह पेश किया जाता है और पाकिस्तान–प्रायोजित अलगाववादियों और आतंकियों के अभिप्राय ही उद्धृत होते हैं। भले ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो, पर पश्चिमी मीडिया ने पहले से ही तय कर लिया है कि कश्मीर में 'आजादी' की पुकार को अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रोत्साहित करना उसका उदारवादी कर्तव्य है। अमेरिका के ही वाशिंगटन पोस्ट और सीएनएन एवं ब्रिटेन के गार्जियन और बीबीसी भी इसी प्रकार भारत को नकारात्मक स्वरूप में दिखाते हैं।

इस विदेशी दुष्प्रचार के कुछ और भी उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आपको याद होगा रामनवमी के दिन हमारे देश में शोभायात्राओं पर पत्थरबाजी हुई थी और भारत के कई शहरों में साम्प्रदायिक हिंसा भड़की थी। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक झूठा सूचना तंत्र तैयार किया गया कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। भारत की गुप्तचर संस्थाओं ने जब ये पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि ये सारे पोस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लिखे जा रहे थे। इस झूठे सूचना तंत्र के पीछे ओपन सोसाइटी फ़ाउंडेशन का नाम सामने आया जिसके मालिक जॉर्ज सोरोस हैं। जॉर्ज सोरोस एक भारत विरोधी अमेरिकी कारोबारी है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस की संस्था भारत में कई वामपंथी मीडिया संस्थानों को फंड देती है।

भारत जब कोरोना की सबसे भयानक मार झेल रहा था ऐसे समय में दुनिया की प्रतिष्ठित टाइम मैगज़ीन ने अपने अंक में "इंडिया इन क्राइसिस" शीर्षक से कवर स्टोरी लिखी जिसके मुखपृष्ठ पर एक तस्वीर छापी गई। अपने कवर पेज पर देश के एक शहर के श्मशान में शव ले जाते परिजनों की तस्वीर प्रकाशित की। जबकि इसी समय में कोरोना से अमेरिका,ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय देशों में हर रोज पांच–छह हजार लोगों की मौत हो रही थी।

(शेष पृष्ठ 33 पर ...)

मजदूरों दुनिया को एक करोः दत्तोपंत ठेंगड़ी

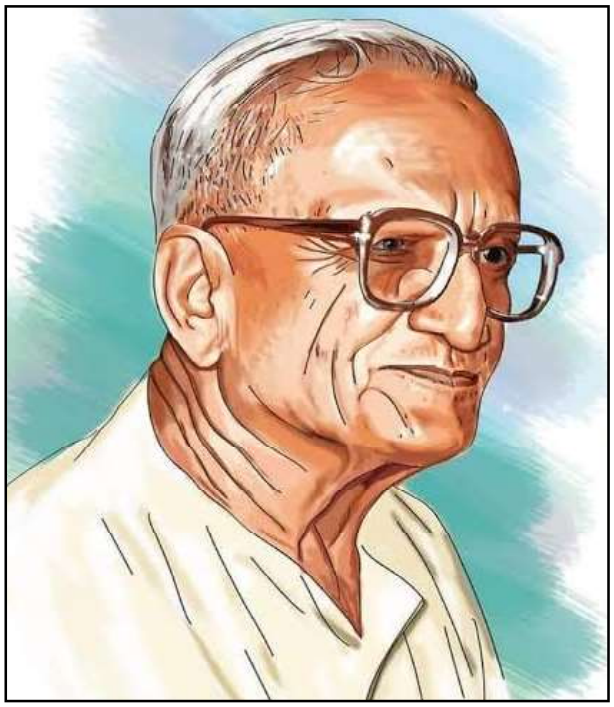

ठेंगड़ी जी दुनिया में कहीं भी जाते थे तो हर जगह मजदूर आंदोलनों के साथ–साथ वहां की सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी करते थे। इसी कारण चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी उनसे श्रमिक समस्याओं पर परामर्श करते थे।

– हेमेन्द्र क्षीरसागर

आजीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म दीपावली के दिन 10 नवंबर, 1920 को महाराष्ट्र में वर्धा जिले के आर्वी गांव में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। 1935 में वे 'वानर सेना' के आर्वी तालुका के अध्यक्ष थे। यह वही समय था, जब उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव राव बलिरम हेडगेवर से हुआ। इस मुलाक़ात ने ठेंगडी के मन में संघ–बीज को बो दिया। ठेंगडी के पिता उन्हें वक़ील बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दत्तोपंत ने एम.ए. और कानून की पढ़ाई के बाद 1941 में अपने जीवन को राष्ट्र व समाज की सेवा में समर्पित कर दिया और संघ प्रचारक बन गए।

प्रचारक–जीवन की शुरुआत में ही दत्तोपंत जी को केरल भेजा गया, वहां उन्होंने 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' का काम किया। केरल के बाद उन्हें बंगाल और फिर असम भेजा गया। यह वही समय था, जब देश भर में वामपंथी अपने प्रभाव का प्रसार कर रहे थे। मज़दूर खेमे में वामपंथियों का भारी प्रभाव था। वाम संगठनों का नारा था 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो.' वहीं, संघ राष्ट्रहित को प्राथमिकता पर रखता था। संघ का मानना था कि मालिक और मज़दूरों का लगातार संपर्क बना रहना चाहिए। देशहित में दोनों की समान भूमिका होनी चाहिए। इसलिए किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों के बीच संवाद जरूरी है. औद्योगिक संगठनों के बंद होने से मज़दूरों का जीवन नरकीय हो जाता है। इसलिए सबको मिलकर देशहित में काम करना चाहिए।

दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी के कहने पर मजदूर क्षेत्र में काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने 'शेतकरी कामगार फेडरेशन' जैसे संगठनों में जाकर काम सीखा। अपने प्रचारक जीवन की शुरुआत ही ठेंगड़ी ने केरल से की थी। केरल में वामपंथियों के प्रभाव और उनके काम के तरीक़ों को वे भलीभांति जानते थे। इसलिए वे साम्यवादी विचार के खोखलेपन को भी जानते थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 'भारतीय मजदूर संघ' नाम से अराजनीतिक संगठन शुरू किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। ठेंगड़ी के प्रयास से श्रमिक और उद्योग जगत के नए रिश्ते शुरू हुए। भारतीय मज़दूर संघ ने देश में वामपंथियों के बनाए मिल मालिक–मज़दूर के बहस को ही बदल दिया। वामदलों के नारे थे, 'चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो' और दुनिया के मजदूरों एक हो, कमाने वाला खाएगा। ' वहीं मजदूर संघ ने कहा, 'देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम' और 'मजदूरों दुनिया को एक करो, कमाने वाला खिलायेगा।'

मजदूर क्षेत्र का बदला दृश्य

संघ की इस सोच ने मजदूर क्षेत्र का दृश्य बदलने का काम किया। ठेंगड़ी जी के प्रयास से मई दिवस के बजाय भारत के कामगार वर्ग की पहचान के प्रतीक भगवान विश्वकर्मा (17 सितंबर) के जन्मदिवस को श्रमिक दिवस के रूप में मानना शुरू किया। दत्तोपंत ने विद्यार्थी और समाज में वंचित वर्ग को जोड़ने का भी काम किया। 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना और उसके प्रभाव को देश के छात्रों में फैलाने का काम ठेंगड़ी ने ही किया। वहीं, समाज को एकजुट करने और एक होकर देश–हित में काम करने के लिए सामाजिक समरसता मंच की नींव रखने का श्रेय भी ठेंगडी को जाता हैं।

भारतीय किसान संघ की स्थापना

ठेंगड़ी का मानना था कि सामाजिक समरसता समाज की एकाग्रता के लिए जरूरी है। समाज जिन्हें वर्षो से अछूत मानकर उपेक्षा करता है, उनको समाज के संपर्क में लाना और समान भाव, समता के आधार पर समाज का संगठन करने के लिए ठेंगड़ी ने अनुसूचित जातियों, जनजातियो के बीच काम करना शुरू किया। ठेंगड़ी ने किसानों में देशहित की भावना जगाने के लिए कहा कि जैसे एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर गौरवान्वित महसूस करता है, उसी तरह किसानों को देश के भीतर देश हित में काम करना चाहिए। भारतीय किसान संघ की स्थापना में ठेंगड़ी की प्रमुख भूमिका रही।

ठेंगड़ी ने 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि दुनिया के साथ विकास की होड़ में भारत अपने देशज विचारों को भूलने नहीं पाए।

देशज विचारों को न भूलें

ठेंगड़ी ने 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि दुनिया के साथ विकास की होड़ में भारत अपने देशज विचारों को भूलने नहीं पाए। स्वदेशी जागरण मंच समय–समय पर देश के नीति निर्माताओं को याद दिलाता रहता था कि उदारवाद को अपनाने में देशहित की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ठेंगड़ी 1951 से 1953 तक मध्य प्रदेश में 'भारतीय जनसंघ' के संगठन मंत्री रहे. उन्होंने मजदूरों के बीच काम करने के लिए राजनीति छोड़ दी। वह 1964 से 1976 तक दो बार राज्यसभा के सदस्य रहे।

चीन और रूस दत्तोपंत से करते थे विचार–विमर्श

ठेंगड़ी जी दुनिया में कहीं भी जाते थे तो हर जगह मजदूर आंदोलनों के साथ–साथ वहां की सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी करते थे। इसी कारण चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी उनसे श्रमिक समस्याओं पर परामर्श करते थे। 26 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगने पर ठेंगड़ी ने भूमिगत रहकर 'लोक संघर्ष समिति' के सचिव के नाते तानाशाही विरोधी आंदोलन को संचालित किया। जनता पार्टी की सरकार बनने पर जब अन्य नेता कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे, तब ठेंगड़ी ने मजदूर क्षेत्र में काम करना पसंद किया।

ठुकरा दिया था 'पद्मभूषण'

एनडीए सरकार की ओर से 2002 में दिए जा रहे 'पद्मभूषण' को उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि जब तक संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार और गुरुजी को 'भारत रत्न' नहीं मिलता, तब तक वह कोई सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे। 14 अक्टूबर, 2004 को उनका निधन हो गया। दत्तोपंत ठेंगड़ी कई भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने हिंदी में 28, अंग्रेजी में 12 और मराठी में तीन किताबें लिखीं। इनमें लक्ष्य और कार्य, एकात्म मानवदर्शन, ध्येयपथ, बाबासाहब भीमराव अंबेडकर, सप्तक्रम, हमारा अधिष्ठान, राष्ट्रीय श्रम दिवस, कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर, संकेत रेखा, राष्ट्र, थर्ड वे प्रमुख हैं। ❑❑

(हेमेन्द्र क्षीरसागर, पत्रकार, लेखक व स्तंभकार)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

'ज्ञान और दान बांटने की सनातनी परंपरा' प्रवासी भारतीयों से किया आह्वान

भारतीय मूल के लोग अपने हुनर और ज्ञान की बदौलत सारी दुनियां में एन.आर.आई. के रूप में सेवायें प्रदान कर रहे हैं। उनमें अधिकांश लोग खासतौर से युवाओं की शिक्षा–दीक्षा भारत में हुई। शिक्षा ग्रहण के बाद, दुनियां के देशों में वह अपनी सेवायें देने तत्पर हुये।

जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के लोग प्रतिवर्ष 2 मार्च को अमेरिका में ''इण्डिया गिविंग डे'' मनायेगें और वहां के एन.आर.आई. के 14 संगठन एकजुट होकर भारत को 24. 7 हजार करोड़ भेजेगें। भारत के विकास के लिए यह एक अच्छी पहल है। हमारे विदेशी मुद्रा के भण्डार बढ़ेंगे। जिससे अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिये देश को सहायता मिलेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रवासी भारतीयों की संख्या 1.75 करोड़ हैं जो दुनियां में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर मैक्सिको 1.18 करोड़ एवं चीन तीसरे स्थान पर 1.07 करोड़ प्रवासी हैं। 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।

9 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी लौटे थे। सबसे बड़ा प्रवासी महात्मा गांधी को माना जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरूआत 2003 दिल्ली से हुई थी। 2019 में प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में आयोजित किया गया था।

आंकड़े बताते हैं कि दुनियां के लगभग 11 देशों में अप्रवासी भारतीय रहते हैं। प्रवासी भारतीयों को आपस में एक नेटवर्किंग तैयार कर एक–दूसरे से जुड़ने की सार्थक पहल भी करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ''सभी प्रवासी भारतीय हमारे एंबेसडर हैं।'' जब प्रधानमंत्री जी ने इन्हें राजदूत की संज्ञा प्रदान की है। तब प्रवासी भारतीयों की राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। वैसे तो कर्तव्यबोध प्रवासी भारतीयों में देश के सम्मान को आगे बढ़ाने का है, जो अमेरिका में रह रहे एन.आर.आई. भाईयों ने करके दिखाया। हमें याद होना चाहिए जिस मातृभूमि ने हमें पढ़ा–लिखाकर इतना काबिल बनाया गया कि हम आज अपने ज्ञान के दम पर दुनियां के अन्य देशों में अपनी सेवायें हर क्षेत्र में दे रहे हैं। इस मातृभूमि के लिए समर्पित रहना है। यहां की भाषा, सांस्कृति, सभ्यता, खान–पान, शिक्षा के कारण ही आज हम इस मुकाम पर हैं। मातृभूमि का ऋण हमारे

भारत दुनियां की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इसको पहले पायदान पर कैसे पहुंचाना है। यह दायित्व हम सब भारतवासियों का है, चाहे देश में हो या देश के बाहर।

– डॉ. जयप्रकाश मिश्र

ऊपर है। उस ऋण को भी चुकाने का अवसर है। विश्व के 110 देशों में रह रहे प्रवासी भारतियों से हमारा आह्वान है कि जिस तरह अमेरिका में रह रहे है हमारे एन.आर.आई. भाईयों ने भारत की आर्थिक मजबूती के लिए 24.7 हजार करोड़ ''इण्डिया गिविंग डे'' मनाकर भेजने का निश्चय किया है। उसी तरह एन. आर.आई. जिस देश में प्रवासी है वहां संगठन बनाकर ''इण्डिया गिविंग डे'' मनाकर, भारत सरकार का अमरीका में रह रहे प्रवासियों की भांति सहयोग करें।

ज्ञात हैं कि भारत मातृभूमि में आज भी अच्छा स्वास्थ, अच्छी शिक्षा, अच्छा आवास, स्वच्छ पानी, पर्याप्त ऊर्जा एवं संतुलित भोजन सभी भारतवासियों को सहज उपलब्ध नहीं हैं। भारत सरकार तो ''सबका साथ, सबका विकास'' के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। यदि आपका आर्थिक सहयोग भारत में रहने वाले आपके भाईयों को मिल जायेगा, तब आपकी मातृभूमि को जिसे दुनिया भर में 'सोने की चिड़िया' कहा जाता है, उसके दिन आपके प्रयास से पुनः लोटेगें।

विश्व के कोने–कोने में रहने वाले हमारे प्रवासी जहां एक ओर हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, गीता आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमारी ज्ञान परम्परा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए आप चाहे तो ''इण्डिया टेकिग डे'' भी 'इण्डिया गिविंग डे' की तरह जहाँ आप प्रवासी हैं उस देश में मना सकते हैं।

भारत में प्राचीनकाल से ही ज्ञान बाटने और दान बटाने की सनातनी परम्परा है। इस शानदान परम्परा को आगे ले जाते हुए प्रवासी भारतीय भाई भारत को दान के रूप में विदेशी मुद्रा भेजे, साथ ही भारतीय ज्ञान परम्परा को हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से दुनियां के विभिन्न देशों को अवगत करायें, प्रचार–प्रसार करें।

चिंतन करें, कि भारत दुनियां की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है इसको पहले पायदान पर कैसे पहुंचाना है। यह दायित्व हम सब भारतवासियों का है, चाहे देश में हो या देश के बाहर। परम वैभवी भारत के लिए जो भारतीय प्रवासियों ने अमेरिका में सगठन बनाकर किया है, इसी तरह के संगठन विश्व के प्रत्येक देश में प्रवासी भारतीय बनाने के लिए संकल्पित हों। ❑❑

लेखक–कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मप्र)

(पृष्ठ 29 से आगे ...)

विदेशी मीडिया में भारत विरोध...

पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ हैशटैग को ट्रेंड करने के लिए बकायदा एक 'ट्वीट आर्मी' है। हजारों की संख्या में हैशटैग को ट्वीट करने और उन्हें ट्रेंड कराया जाता है। यही नहीं दुनिया भर में बैठे पाकिस्तानियों ने फेक लोकेशन से 1 लाख से ज़्यादा भारत विरोधी कमेंट लिखे। जानकारी के मुताबिक 30 देशों से 40 भाषा और करीब 46 हज़ार प्रोफाइल के जरिये भारत के खिलाफ तमाम आधारहीन बातें दुनिया भर में फैलाई गई। जाहिर है खाड़ी देशों से भारत के संबंध बिगाड़ने की साजिश के तहत पाकिस्तान से नूपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग को ट्रेंड कराया गया।

ऐसे में निम्न सुझावों के जरिये भारत विरोधी स्वर रोका जा सकता है–

1. भारत में विभिन्न धर्म, संस्कृतियाँ, भाषाएँ और उत्सव हैं, इस विविधता और सुंदरता को हम मीडिया में अपनी शक्ति और समृद्धि के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं।
2. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संगठनों जैसे यूनेस्को, ब्रिक्स, विश्व व्यापार संगठन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों में भारत अपने विकास, शिक्षा, संस्कृति की समृद्धि को जोरदार तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं।
3. विदेशी मीडिया को विशाल और समृद्ध भारत के विषय में बहुत कम जानकारी है। समय समय पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं विदेशी मीडिया संस्थानों को भारत में भारत दर्शन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।
4. विभिन्न देशों में स्वतंत्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, दीपावली पर भारतोत्सव और व्यापार मेले आयोजित किए जा सकते हैं जिस से वहाँ के नागरिकों को भारत के बारे में जानने को उत्सुकता पैदा हो और भारत के विरोधी मीडिया प्रचार को प्रतिकार का सामना करना पड़े।
5. एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि विदेशी मीडिया में भारत का निवेश प्रारम्भ हो। तभी विदेशों में भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगेगा।
6. वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुंबई में चल रही बैठक और भविष्य में आयोजित होने वाले जी 20 के होने वाले सम्मेलन में भारत के पास अवसर हैं कि भारत के सफल लोकतन्त्र, विकास और राजनीतिक विविधता के हमारे लोकतन्त्र में बहुत समवेशी संदर्श को विश्व के पटल पर रखे।
7. सरकार 'दूरदर्शन इंटरनेशनल' चैनल खोलने के प्रस्ताव पर अगर शीघ्रता और बुद्धिमानी से अमल करे तो भारत के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय लोकमत बनाना संभव है।
8. केंद्र सरकार का सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वययन मंत्रलाय वह सभी आंकड़े तैयार कर अंक जारी करे, जिनके बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई जाती है। ❑❑

विनोद जौहरी: पूर्व अपर आयकर आयुक्त

ग्लाइफोसेट के सामान्य उपयोग पर लगी रोक

स्वदेशी जागरण मंच ने जताया आभार

F.No. 08-81/2021-CIR-I
भारत सरकार
Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
Department of Agriculture & Farmers Welfare
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION, QUARANTINE & STORAGE
केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवम पंजीकरण समिति
Central Insecticides Board and Registration Committee
एन. एच. 4, फरीदाबाद (हरियाणा)-121001
N.H. IV, FARIDABAD (HARYANA)-121001
******

Dated: 16th September, 2022

PUBLIC NOTICE

Subject- Definition of non-crop area framed by the sub-committee constituted by DA&FW under the Chairmanship of Plant Protection Adviser -regarding.

The Registration Committee in its 440th meeting held on 03.08.2022 at agenda item No. 10.9 has approved the definition of non-crop area as under:

"All areas where a crop or any intentionally planted vegetation is not grown such as;

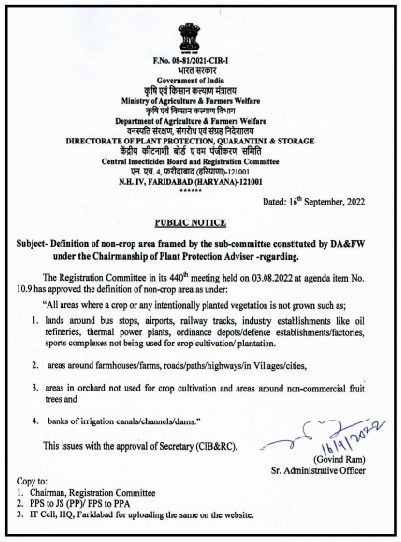

1. lands around bus stops, airports, railway tracks, industry establishments like oil refineries, thermal power plants, ordinance depots/defence establishments/factories, sports complexes not being used for crop cultivation/ plantation.
2. areas around farmhouses/farms, roads/paths/highways/in Villages/cities,
3. areas in orchard not used for crop cultivation and areas around non-commercial fruit trees and
4. banks of irrigation canals/channels/dams."

This issues with the approval of Secretary (CIB&RC).

16/9/2022
(Govind Ram)
Sr. Administrative Officer

Copy to:
1. Chairman, Registration Committee
2. PPS to JS (PP)/ PPS to PPA
3. IT Cell, HQ, Faridabad for uploading the same on the website.

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में ग्लाइफोसेट और इसके अन्य उत्पादों के आम उपयोग प्रतिबंधित किये जाने पर स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है। मनुष्यों और जानवरों में कैंसर सहित कई तरह की गंभीर बीमारियों का स्रोत कारसिनोजॉन और अंतःस्रावी अवरोधक ग्लाईफोसेट को प्रतिबंधित किये जाने की मांग को लेकर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन के नेतृत्व में चेंज डॉट ओआरजी (change.org) पर ऑनलाईन याचिका शुरू की गई थी। डॉ. महाजन के नेतृत्व में 2 लाख 2 हजार 273 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित विरोध प्रपत्र केंद्रीय कृषि मंत्री को सौंपा गया था।

सरकार ने मानव/जानवरों के लिए स्वास्थ्य संबंधित खतरों और जाखिम को देखते हुए खरपतवारनाशक हर्बिसाइड ग्लाईफोसेट और इसके अव्यव के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी 25 अक्टूबर 2022 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्लाईफोसेट का सामान्य उपयोग प्रतिबंधित है और कोई भी व्यक्ति कीट नियंत्रण परिचालकों (पीसीओ) को छोड़कर ग्लाईफोसेट का उपयोग नहीं करेगा। कंपनियों को ग्लाईफोसेट और उसके उत्पादों के लिए दिये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र को पंजीकरण समिति को वापिस करने के लिए कहा गया है, जिससे लेबल और पत्रक पर बड़े अक्षरों में चेतावनी को शामिल किया जा सके। अधिसूचना में कहा गया है ''पीसीओ के माध्यम से ग्लाईफोसेट फार्मूलेशन के लिए अनुमति दी जायेगी।''

जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनियों को प्रमाण पत्र वापिस करने के लिए 3 महीने को समय दिया गया है। अन्यथा कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

स्वदेशी जागरण मंच की ऑनलाईन याचिका में ग्लाईफोसेट के खतरों को रेखांकित करते हुए कहा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतरराष्ट्रीय कैंसर शोध एजेंसी (आईएआरसी) ने 2015 में ग्लाईफोसेट को मानव कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है। मोनसेंटो/बायर कंपनी के खिलाफ ग्लाइफोसेट आधारित हर्बिसाइड के उपयोगकर्ताओं द्वारा नुकसान के लिए 1.4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, क्योंकि उन्होंने वादकारियों में गैर–हॉजकिन्स लिंफोमा सहित 10 विभिन्न प्रकार के कैंसर विकसित किए थे। इसे देखते हुए पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कई अन्य राज्य उपभोक्ताओं, किसानों और पर्यावरण के लिए अपनी चिंताओं के कारण ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने की ओर बढ़ गए हैं। चाय उत्पादक राज्य केरल ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। वहीं पश्चिम बंगाल ने ग्लाइफोसेट के उपयोग को केवल 6 चाय उत्पादक जिलों तक सीमित कर दिया है।

सरकार ने केवल पंजीकृत पीसीओ द्वारा ग्लाइफोसेट के आवेदन को सीमित करने का निर्णय लिया, जिसका अर्थ है कि किसानों को कोई सीधी बिक्री नहीं की जा सकती है। पीसीओ भी चाय बागानों और गैर फसल क्षेत्रों को छोड़कर खेतों में इस हत्यारा शाकनाशी को नहीं पहुंचा सकते हैं।

इस बीच सरकार द्वारा जारी एक अन्य सार्वजनिक नोटिस के अनुसार गैर फसली क्षेत्रों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

सभी क्षेत्र जहां कोई फसल या कोई जानबूझकर रोपित वनस्पति नहीं उगाई जाती है जैसे–

- बस स्टॉप, हवाई अड्डों, रेलवे पटरियों, तेल रिफाइनरियों, थर्मल पावर प्लांट, ऑर्डिनेंस डिपो/रक्षा प्रतिष्ठानों/फैक्ट्रियों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
- फार्महाउसों/फार्मों, सड़कों/पथों/राजमार्गों/गांवों/शहरों के आसपास के क्षेत्र,
- बाग के क्षेत्र, सिंचाई नहरों/चैनलों/बांधों के किनारे इसका उपयोग नहीं होगा।

मसलन ग्लाइफोसेट का उपयोग केवल चाय बागानों और गैर–फसल क्षेत्रों में ही किया जायेगा। ❑❑

ग्लाइफोसेट के आम उपयोग पर रोक जनहित में: स्वजाम

स्वदेशी जागरण मंच ने खर–पतवार नाशक ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नागरिकों खासतौर पर किसानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी था। ज्ञात हो कि स्वदेशी जागरण मंच ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहा है, क्योंकि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है।

स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि खर–पतवार नाशक ग्लाइकोफास्फेट के उपयोगकर्ताओं को नुकसान के संबंध में मोन्सांटो और बेयर के खिलाफ 1.4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जो वादियों के विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे रोगों से प्रभावित होने से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने दृढ़ता से ग्लाइफोसेट एवं इसके यौगिकों के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को लोगों के हित में निर्णय लेने के लिये धन्यवाद देता हूं। ''

गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने ग्लाइफोसेट एवं इसके यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

https://www.msn.com/en-in

जीएम सरसों स्वदेशी नहीं: स्वजामं

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) की सिफारिश के बाद भारत में जीएम सरसों के पर्यावरण रिलीज को मंजूरी दे दी है। जीएम सरसों की किस्म डीएमएच–11 को सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (सीजीएमसीपी) द्वारा विकसित किया गया है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन है।

डीएमएच–11 किस्म 1.0–1.3 टन/हेक्टेयर के मौजूदा औसत से 28 प्रतिशत अधिक उपज लाभ का वादा करती है। परीक्षणों में प्रति हेक्टेयर 2.7 टन उपज दिखाई गई है। हालांकि यह किस्म खेती की कम लागत के लिए अधिक उपज का वादा करती है, लेकिन इसे लोगों की सुरक्षा से समझौता करके हासिल नहीं किया जा सकता है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री को जीएम सरसों की मंजूरी पर पुनर्विचार करने के लिए पत्र लिखा है।

पत्र में डॉ. महाजन ने कहा है, "जीएम सरसों के स्वदेशी होने का दावा और भारत में विकसित किया गया है, गलत है क्योंकि दो जीन 'बर्नसे' और 'बारस्टार' बैसिलस एमाइलोलिफेशियन्स नामक मिट्टी के जीवाणु से प्राप्त होते हैं। बार–बारस्टार–बर्नेज जीन 'बायर क्रॉप साइंस' की पेटेंट तकनीक है। बायर कोई स्वदेशी कंपनी नहीं है।"

पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि किसानों को हर्बिसाइड ग्लइफोसेट का उपयोग करना होगा जो फसल प्रतिरोधी है और हर्बिसाइड के इस उपयोग से कंपनी को लाभ होगा। यह फसल मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के लिए भी हानिकारक हो सकती है।

डॉ. महाजन ने उल्लेख किया कि गैर–जीएमओ टैग ने भारत को यूरोपीय देशों को खाद्य निर्यात करने में मदद की है जहां जीएमओ प्रतिबंधित है। जीएम सरसों के आने से, भारत गैर–जीएमओ टैग खो देगा और इससे निर्यात में बाधा आएगी।

https://www.krishakjagat.org/national-news/panic-over-gm-mustard-gm-mustard-not-swadeshi-swadeshi-jagran-manch

2025 तक हर युवा को रोजगार का लक्ष्य

स्वदेशी जागरण मंच ने संगठन के विस्तार की योजना तय की है। मंच की ओर से 'स्वावलंबी भारत" अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में रोजगार सृजन केंद्र खोले जाएंगे। रायपुर के बाद दुर्ग में रोजगार केंद्र खोला

गया है, जो युवाओं को रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। छह महीने के भीतर बाकी जिलों में भी केंद्र खोले जाएंगे। ज्यादातर केंद्र विश्वविद्यालय और कालेज में प्रस्तावित हैं।

स्वदेशी जागरण मंच का यह कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न् रोजगार व स्व–रोजगार योजनाओं से अलग है। 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष तक हर युवा के पास रोजगार–स्वरोजगार हो, इस लक्ष्य को लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। आंकड़ों के अनुसार देश में 15 से 29 वर्ष की उम्र के 37 करोड़ युवा हैं। इनमें से केवल सात प्रतिशत युवाओं के लिए ही सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं। विडंबना है कि अधिकतर युवाओं में केवल नौकरी करने की मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए दो हजार से अधिक युवाओं की टोली काम कर रही है। ये युवा दो–दो अन्य युवाओं को स्व–रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

संघ की पिछले महीने 10 से 12 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वयक बैठक रायपुर में आयोजित हुई थी। इस बैठक में संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत शामिल हुए थे। इसमें तय हुआ था कि संघ के शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय व सामाजिक परिदृश्य के साथ–साथ देशभर में स्वावलंबी भारत अभियान, गोसेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता आदि विषयों पर तेजी से काम किया जाएगा।

राज्य के सभी जिलों में स्वदेशी जागरण मंच की इकाई बनाई जा रही है। मंच के स्वयंसेवक स्कूल–कालेज के विद्यार्थियों के पास जा रहे हैं। जो विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। युवाओं को स्टार्टअप, मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की जानकारी दी जा रही है। स्वावलंबी भारत कार्यक्रम में 23 संगठनों द्वारा मिलकर यह अभियान चलाया जा रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच ने प्रदेश में अभियान तेज कर दिया है। 2025 तक हर युवा तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर के बाद प्रदेश के दुर्ग में दूसरा स्वरोजगार केंद्र खोला गया है। जल्द ही प्रदेश के हर जिले में रोजगार सृजन केंद्र खोले जाएंगे।

https://www.naidunia.com/chhattisgarh/raipur-cg-news-swadeshi-jagran-manch-aims-to-provide-employment-and-self-employment-to-every-youth-by2025-7900307

वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट गैर–जिम्मेदाराना, शरारतपूर्ण

स्वदेशी जागरण मंच ने वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट–2022 को "गैर–जिम्मेदाराना और शरारतपूर्ण" बताते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह "भारत को बदनाम करने के लिए" इसके प्रकाशकों के खिलाफ कार्रवाई करे। वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट–2022 में 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से बहुत पीछे है जबकि भारत में बच्चों में 'चाइल्ड वेस्टिंग रेट' (ऊंचाई के हिसाब से कम वजन) 19.3 प्रतिशत है जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे अधिक है। हाल ही में गैर–सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्डवाइड' (आयरलैंड) और वेल्ट हंगर हिल्फ़ (जर्मनी) ने यह रिपोर्ट जारी की है।

स्वदेशी जागरण मंच ने रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "जर्मन गैर–सरकारी संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ़ ने एक बार फिर वैश्विक भूख सूचकांक विषय पर 121 देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसे भारत को बदनाम करने के लिए बेहद गैर–जिम्मेदाराना तरीके से तैयार किया गया है।"

मंच ने कहा, "रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर और दोषपूर्ण है। यह आंकड़ों के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि विश्लेषण और कार्यप्रणाली के नजरिए से भी हास्यास्पद है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में 116 देशों की सूची में भारत 101वें स्थान पर था।" मंच ने आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट इसके प्रकाशकों के दुर्भावनापूर्ण इरादे को स्पष्ट करती है। बयान में कहा गया है, "स्वदेशी जागरण मंच इस रिपोर्ट के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त करता है और सरकार से इसे खारिज करने तथा उन संगठनों के खिलाफ उचित

कार्रवाई करने का अनुरोध करता है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा के बारे में झूठ फैलाकर देश को बदनाम कर रहे हैं।"

https://www.enavabharat.com/india/global-hunger-index-report-irresponsible-mischievous-swadeshi-jagran-manch-633544/

ऋषि सुनक ने रचा इतिहास, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के पीएम

ऋषि सुनक कंजरवेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुन लिए गए। इस तरह वह यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। सुनक को 190 से अधिक सांसदों ने समर्थन दिया। वहीं उनकी प्रतिद्वंद्वि पेनी मोर्डंट 100 सांसदों का जरूरी समर्थन हासिल करने में विफल रहीं और इस रेस से बाहर हो गईं।

पेनी मोर्डंट ने एक ट्वीट में घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हो रही हैं और सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में समर्थन दे रही हैं।

कंजरवेटिव पार्टी के 'बैकबेंच' सांसदों की प्रभावशाली 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी ने संसद परिसर में घोषणा की कि उन्हें केवल एक नामांकन मिला है, लिहाजा नेतृत्व प्रतियोगिता में सुनक विजयी रहे हैं। इसका मतलब है कि बकिंघम पैलेस में महाराजा चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के रूप में लंदन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय 10, डाउनिंग स्ट्रीट में कदम रखेंगे।

सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री और देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। वह ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री भी हैं। हालांकि देश का वित्त मंत्री रहने के दौरान उन्होंने अपने धर्म को लेकर शायद ही कभी बात की हो।

सुनक की जीत उनके राजनीतिक भाग्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है, जो पिछले महीने सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों का समर्थन नहीं मिलने के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस से चुनाव हार गए थे। कंजरवेटिव पार्टी में ट्रस के नेतृत्व के खिलाफ खुला विद्रोह हो गया था, जिसके चलते सिर्फ 45 दिन तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

सुनक का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। भारतीय मूल के उनके पिता यशवीर रिटायर्ड डॉक्टर हैं, जबकि मां ऊषा सुनक फार्मासिस्ट हैं। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा था कि वह 'देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने, अपनी पार्टी को एकजुट करने और देश के लिए काम करना चाहते हैं।' सुनक ने प्रचार अभियान में कहा था, 'मैं समस्याओं से निपटने के लिए आपसे एक अवसर मांग रहा हूं।'

सुनक ने विरासत में मिलने वाले आर्थिक संकट का

संदर्भ देते हुए कहा कि वह पिछले सप्ताह ट्रस द्वारा घोषित 'विनाशकारी' कर कटौती वाले बजट का अनुपालन कर सफल नहीं हो सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'ब्रिटेन महान देश है लेकिन बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इसलिए मैं पार्टी का नेता और आपका अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए मैदान में हूं।'

सुनक के दादा–दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मस्थान आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में स्थित है। इस प्रकार नए ब्रिटिश नेता एक भारतीय और एक पाकिस्तानी दोनों है।

क्वीन लायनेस 86 नामक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, 'सुनक गुजरांवाला का एक पंजाबी खत्री परिवार है, जो अब पाकिस्तान में है। ऋषि के दादा रामदास सुनक ने 1935 में नैरोबी में क्लर्क की नौकरी के लिए गुजरांवाला को छोड़ दिया।' परिवार की जानकारी मुहैया कराने वाली क्वीन लायनेस 86 के अनुसार, रामदास की पत्नी, सुहाग रानी सुनक 1937 में केन्या की यात्रा करने से पहले, अपनी सास के साथ गुजरांवाला से पहले दिल्ली चली गईं। ऋषि का जन्म 1980 में साउथेम्प्टन में हुआ।

https://hindi.news18.com/news/world/rishi-sunak-will-be-first-indian-origin-prime-minister-of-united-kingdom-4793019.html

जीएम सरसों का विरोध शुरु, दिल्ली में होगी 'किसान गर्जना रैली'

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशांगिक संगठन भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा रायपुर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के किसान पदाधिकारियों की बैठक ली और जीएम सरसों की खेती को लेकर मिली अनुमति को लेकर विरोध प्रकट किया।

बैठक में तय किया गया कि किसान अपनी तीन मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ से दो हजार किसान सम्मिलित होंगे। इससे पहले किसान राज्यों के कृषि मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर जीएम सरसों का विरोध करेंगे।

संघ ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि अगर इसकी खेती करने की अनुमति को निरस्त नहीं किया जाता है तो देशभर में आंदोलन किया जाएगा। बैठक में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष युगल किशोर मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री तुलाराम और प्रदेश महामंत्री नवीन शेष समेत अन्य मौजूद रहे।

मोहिनी मोहन ने कहा कि किसानों ने भरपूर उत्पादन कर देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है किंतु किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है लेकिन किसानों के लागत के आधार पर मूल्य मिलना चाहिए।

2018 में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अभी प्रति वर्ष छह हजार रुपये मिल रहे हैं। इस योजना की राशि की बढ़ाने की मांग की जाएगी। कृषि उत्पादों में जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर भी आंदोलन जारी है।

मोहिनी मोहन ने कहा कि जीएम यानी जेनेटिकली माडिफाइड सरसों को लेकर कृषि वैज्ञानिक भी असमंजस में हैं। इसके अधिक उपजाऊ होने का दावा गलत निकला तो कहा गया कि पुरूष बांझपन को दूर करने में उपयोगी होगा। दरअसल इसके नफा नुकसान को लेकर कोई मापदंड ही तय नहीं किया गया है। इसे उगाने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ सकता है।

इस सरसों का मधुमक्खियों, कीट पतंगों, परागण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होगा इस पर कोई अनुसंधान नहीं हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) के पास कोई सबूत नहीं है और अनुमति दे दी। इससे पहले बीटी बैंगन का विरोध किया गया था और सरकार ने उसकी खेती का निर्णय वापस ले लिया था। जीएम सरसों की अनुमति पर केंद्रीय मंत्री ने अभी हस्ताक्षर नहीं किया है। पहले तो राज्यों से अनापत्ति मांगना चाहिए। भारतीय किसान संघ जीएम सरसों के विरोध के लिए कृत संकल्प है।

https://www.naidunia.com/chhattisgarh/raipur-protest-against-gm-mustard-begins-kisan-garjna-rally-will-be-held-in-delhi-7911495

दिवालिया होने की कगार पर क्रिप्टो

दुनिया की तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स ने अमेरिका में दिवालिया प्रक्रिया के तहत आवदेन कर दिया है। ये ऐसे समय पर किया गया है, जब बिनेंस से डील टूटने के चलते कंपनी फंड की कमी का सामना कर रही थी। एफटीएक्स के साथ जुड़े हुए हेज फंड अल्मेडा रिसर्च और उससे जुड़ी हुई अन्य कंपनियां भी इस आवेदन का हिस्सा है। इसके साथ ही कंपनी के सीईओ और संस्थापक सैम बैंकमैन फ्राइड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बैंकमैन फ्राइड की संपत्ति में भी बड़ी गिरावट आई है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अनुसार, दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन करने से पहले उनकी संपत्ति 23 बिलियन डॉलर थी, जिसमें अब बड़ी गिरावट आ चुकी है। समाचार एजेंसी एपी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एफटीएक्स में चल रही दिक्क़तों के पीछे कंपनी कुछ हद तक खुद ही जिम्मेदार है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जांच कर रहे हैं कि क्या कंपनी के परिचालन में कोई आपराधिक कृत्य किया गया है।

https://www.jagran.com/business/biz-world-third-largest-crypto-exchange-ftx-apply-for-bankruptcy-bitcoin-tumbles-23198976.html

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा देश

भारत ने 2022 की पहली छमाही में सौर ऊर्जा उत्पादन के जरिये ईंधन लागत में 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत की है। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में 19.4 मिलियन टन कोयले की बचत हुई है।

एनर्जी थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट में पिछले दशक से लेकर अब तक वैश्विक सौर ऊर्जा परिदृश्य का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पता चला है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से पांच एशिया में हैं। एशिया में चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और वियतनाम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बने हुए हैं। ❑❑

https://www.jagran.com/business/biz-india-saved-over-usd-4-bn-in-fuel-costs-through-solar-power-claims-report-23194289.html

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

योजना बैठकें

सचित्र झलक

गया, बिहार

काशी प्रांत

मऊ, उत्तर प्रदेश

मेरठ, उत्तर प्रदेश

मुजफ्फरपुर, बिहार

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 नवंबर 2022
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

दुर्ग, मध्य प्रदेश

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

करीम नगर, तेलंगाना

रायपुर, छत्तीसगढ़

मऊ, उत्तर प्रदेश

सवाई माधोपुर, राजस्थान

उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

Advt

Printed and published by Dr. Ashwani Mahajan on behalf of Swadeshi Jagran Samiti and printed at Competent Binders, Naveen Shahdara Delhi-32, published at Dharmakshetra, Sector-8, R.K. Puram, New Delhi-110022, editor Ajey Bharti